● वर्ष-3

● अंक-33

रायपुर, शनिवार 16 सितंबर 2023

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› नकसीर के घरेलु उपचार

मुख्यमंत्री बेल पर हैं, उनकी निजी सचिव जेल में: नड्डा

परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का हुआ जशपुर से आगाज, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे नेतृत्व

रायपुर/जशपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में जशपुर से प्रारंभ हुआ। इस मौके पर जनसमुदाय को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम सब लोग जिस समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, आज जो परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं उसे भगवान बालाजी का आशीर्वाद मिले ताकि हम सफल हो। उ्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर बढ़े। एक मुख्यमंत्री सीडी कांड में में बेल पर उसका निज सचिव जेल में है ऐसी सरकार को बने रहने देना है क्या? उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा मित्रों जब हम बात करते हैं भूपेश बघेल की, तो बोलिए कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी जन घोषणा पत्र की बातें पूरी की है क्या? जो कह कर आए थे उसकी विपरीत काम किया कि नहीं किया बताइए? 1500 रुपए प्रतिमाह माताओ को मिल गए क्या? गरीब माता बहनों को चार मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा कहा वह मिला क्या? मैं किसानों से पूछना चाहता हूं की भूमिहीन किसानों को आदिवासी किसानों को जमीन देंगे कहा वह जमीन आपको मिला

क्या?

दिलीप सिंह जूदेव को याद किया

उ्होंने कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव महान नेता तो थे ही महान आत्मा तो थे ही लेकिन वह महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले थे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वह हमारे लोकसभा ,राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम लोग जानते हैं यहां बहुत लोग जय जुदेव के नाम से अभिवादन करते हैं। वह केवल नेता नहीं थे वह देश को देश की एकता को मजबूत करने वाले नेतृत्व कर्ता भी थे। घर वापसी, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दाव में लगा देने वाले नेता श्री दिलीप सिंह जूदेव थे।

भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति के रात्रि भोज के निवेदन को ठुकरा दिया

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जी-20 की बैठक में राष्ट्रपति जी के रात्रि भोज के निवेदन को ठुकरा दिया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लाल किला में प्रधानमंत्री के अभिभाषण को ठुकरा दिया यह ऐसे लोग हैं जो भारत और भारत के गौरव से जुड़ी हुई चीजों से नफरत करते हैं। इन्हे सत्ता में बने रहने का कोई हक नही है। अब भ्रष्टाचार पर बात करते है प्रदेश में 2161 करोड़ का शराब घोटाला किया गया, 5000 करोड़ का चावल घोटाला किया गया, कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, गरीब कल्याण योजना में घोटाला, गोबर में घोटाला हुआ अरे भैया जिसने गौ माता को नहीं छोड़ा और वह आपको छोडेंगे क्या?

प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि को रोका

आज किसानों की सहायता के लिए किसान सम्मान निधि, देश के करीब 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हर चौथे महीने 2000 और साल के 6000 देने का फैसला किया है। आज कोई किसान किसी साहूकार के भरोसे नहीं रहता । जल जीवन मिशन के तहत लगभग 10 करोड लोगों तक जल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ घर बना रहे हैं वहीं इसी के लिए 14 लाख 80,000 घर बनाने के लिए केंद्र ने स्वीकृति दी है लेकिन भूपेश सरकार ने स्वीकृति रोक कर रखी है। मुझे जानकर दुख होता है कि यह किसी हितग्राही परिवार के पांच लोग कच्चे मकान में दब कर मर गए इसके जिम्मेदार भूपेश सरकार है।

मुख्यमंत्री बघेल के दांत, खाने के और दिखाने की और है खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए झूठी घोषणा माता को 1500 दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। श्री नड्डा ने कहा यह परिवर्तन यात्रा क्यों है? यह परिवर्तन यात्रा इसलिए है क्योंकि हम पहले भी आपकी सेवा किए हैं और आगे भी आपकी सेवा करेंगे और वादा करते हैं गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम किया है उसे छत्तीसगढ़ की धरा में उतारेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। किसानों का सशक्तिकरण करेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। युवाओं को आगे बढ़ने वाला काम करेंगे और छत्तीसगढ़ की परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार लोगों के सामने लाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें उखाड़ फेंके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली यात्रा की शुरुआत मां दंतेश्वरी की आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ था। आज यात्रा का चौथा दिन है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा और तेज बह रही है। परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि 2003 में परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ था और आज फिर जशपुर की धरती से परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है।

2003 की परिवर्तन यात्रा को आज फिर से हमें दोहराना होगा: सरोज

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा को भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जशपुर पहचाना जाता था हमारे कुमार साहब के नाम से। स्वर्गीय दिलीप सिंह जी देव जी ने जशपुर की संस्कृति को बचाने का काम किया है। 2003 में भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी और आज भी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। दिलीप सिंह जी देव ने अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा था कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए और परिवर्तन हुआ भी।

कोरोना काल में घर-घर शराब पहुंच रही थी: बृजमोहन

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नहीं 2018 में अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था लेकिन यह सरकार शराब बंदी करने के बजाए कोरोना काल में घर-घर शराब पहुंच रही थी। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार करने का काम किया था, प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, प्रदेश के बुजुर्ग को 1500 रूपए एवं विधवा बहनों को 1000 रूपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, ऐसे 36 वादे कांग्रेस ने किया था लेकिन कोई भी वादा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है।

चुनावी मुद्दा बना कर घोटाला करने वाली है भूपेश सरकार-पीयूष गोयल

■ **केंद्रीय मंत्री ने धान के मुद्दे पर किया प्रेस कांफ्रेस**

रायपुर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शाम रायपुर पहुंचे और प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल धान के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार व सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि धान के मुद्दे पर केंद्र पर आरोप लगाना बेबुनियाद है। केंद्र सरकार छल नहीं करती है। भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। अभी हाल ही में राज्य के खाद्य सचिव ने पत्र लिखकर केंद्र की कमियां गिनाई थी। 65 हजीर टन चावल की अफरा तफरी पकड़ी गई थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है।

मुख्यमंत्री के केन्द्र को 86 लाख टन चावल नहीं लेने का आरोप लगाने पर उन्होंने कहाकि राज्य सरकार पहले 61 लाख टन धान देने का वादा किया था। अभी तक सिर्फ 53 लाख टन धान मिल पाया है। केंद्र सरकार 100 लाख टन चावल खरीदने को तैयार है। भूपेश सरकार केंद्र पर आरोप लगाते हैं। पिछला टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएं और आरोप लगाते है कि केंद्र चावल नहीं ले रही है। किसानों के बायोमेट्रिक पंजीयन के मामले में राज्य सरकार विरोध कर रही है। केंद्र ने पारदर्शिता के लिए यह लागू किया है। लेकिन राज्य सरकार सोची समझी साजिश के तहत बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे है। साफ है राज्य सरकार घोटाला करने वाली है। उन्होंने भूपेश सरकार पर अधिक मात्रा में धान खरीगी के नाम पर किसानें से फरेब करने का

आरोप लगाया।

केन्द्रीय मंत्री ने राईस मिलों के द्वारा धान के कम चावल देने की जानकारी की जांच करने एक समिति के गठन का ऐलान किया।

छत्तीसगढ़ में आने वाली है भाजपा सरकार

महंगाई के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि होलसेल प्राइज इंडेक्स निगेटिव है। माइनस में जा चुका है। यूपीए सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई थी। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में आरबीआई में सबसे कम ब्याज दर दिया गया है। भूपेश सरकार झूठ और फरेब पर टिकी है। धान खरीदी की 100त्न धनराशि केंद्र सरकार देती है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पीयूष गोयल ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने वाली है। इससे प्रदेश के किसानों की समस्याओं का अंत होगा।

रायपुर। सीएसआईडीसी के अध्यक्ष डॉ. डॉ नंद कुमार साय ने आज औद्योगिक संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में बैठक की। कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए डॉ. नंदकुमार साय ने सभी औद्योगिक संगठनों को औद्योगिक अधोसंरचना को उत्कृष्ट श्रेणी पर लाने सभी उद्योगों को एक अच्छी सुविधा प्रदान करने और भविष्य में उन्हें अपने उद्योग चलाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इस संबंध में चर्चा की गई। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अश्विन गर्ग एवं विभिन्न उद्योग संघ के प्रतिनिधियों ने सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले स्थानीय कर से उद्योगों को मुक्त करने पर छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया।

प्रमुख समाचार

राजस्थान अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार में नंबर वन:अनुराग

नईदिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से वार्तालाप करते हुए ठाकुर ने

गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान में लूट की खुली छूट है। राजस्थान आज अवैध खनन में नंबर वन है, गैंग रेप, गैंग वार, माता बहनों के खिलाफ अपराध, पेपर लीक, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार में भी नंबर वन है। यहां की जनता गहलूट सरकार से त्रस्त है और जल्द से जल्द इनसे छुटकारा पाना चाहती है। सही मायने में राजस्थान में मुख्यमंत्री का इक़बाल ख़त्म हो गया है। मीडिया के लोगों के विरोध और बहिष्कार को कांग्रेस को पुरानी मानसिकता से जोड़ते हुए ठाकुर ने कहा, इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया था। इंदिरा गांधी ने मीडिया को कुचल कर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाने का कार्य किया था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से क्क गवर्नमेंट में कपिल सिब्बल जी ने आर्टिकल 66ए को बिना चर्चा के पास किया था।

चंद्रशेखर राव ने संसद में महिला आरक्षण की मांग की

नईदिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद और राज्य विधानमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33 प्रतिशत कोटा की मांग की है। तेलंगाना के

मुख्यमंत्री ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की भी मांग की है। पांच दिवसीय संसद का विशेष सत्र 18-22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान ने महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव को दूर करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रावधानों की परिकल्पना की है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर रही है। केसीआर ने कहा कि समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानमंडलों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।

द्रमुक सांसद एक महीने में जमीन खाली करे: अदालत

नईदिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को द्रमुक सांसद डॉ. वी कलानिधि को एक महीने के भीतर यहां सरकार की एक संपत्ति को खाली करने तथा उसका कब्जा सौंपने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कलानिधि द्वारा

दायर याचिकओं का निस्तारण किया जिसमें उन्होंने प्राधिकारियों को उनकी संपत्ति में दखल देने से रोकने का अनुरोध किया था जहां एक अस्पताल बना हुआ है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को भूमिहीन गरीब व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के पिता एन वीरस्वामी एक पूर्व मंत्री हैं और कलानिधि खुद संसद सदस्य हैं। याचिकाकर्ता एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मौजूदा मामलों में राजनीतिक पद के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि अदालत कई मामलों में देख रही है कि सरकारी जमीन समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली सदस्यों को आवंटित की जाती है जो संभवत- वास्तविक आवेदक नहीं होते।

राजनीति में हमारा प्रमुख दुश्मन बीजेपी: वेणुगोपाल

नईदिल्ली। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कल हम हैदराबाद में पहली सीडब्ल्यूसी (कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक) करेंगे जिसमें

आगामी चुनाव तैयारियों पर चर्चा होगी। हमें पूरा यकीन है कि हम तेलंगाना समेत पांच राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना के अलावा इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। कांग्रेस चुनावों को लेकर लगातार रणनीति बना रही और इन राज्य के नेताओं के साथ बैठक कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान भाजपा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चेंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निश्चित रूप से हमारे पास पुराना अनुभव है। हमारी लड़ाई पीएम नरेंद्र मोदी से है। राजनीति में हमारा प्रमुख दुश्मन बीजेपी और उनकी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि वे (केसीआर की पार्टी) संसद में अलोकतांत्रिक कानूनों का समर्थन करते हैं। केसीआर की पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है, वे वास्तव में लोगों के खिलाफ हैं।

मोदी सरकार ने दी 12 सुखोई-30 खरीद को हरी झंडी

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने आज भारतीय वायु सेना (ड्ढस्न) के लिए 12 यूएस-30 एमकेआई की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। विमान में आवश्यकता के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक

स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। विमान में आवश्यकता के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल होगी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि ये भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक एसयू-30 एमकेआई विमान होंगे जो कई भारतीय हथियारों और सेंसर से लैस होंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि 15 सितंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से खरीदें श्रेणी के तहत की जाएंगी, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।

-

वैश्विक खतरा बन सकता है खालिस्तान आतंकवाद, कनाडा पर लगाम जरूरी

इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो एक डरावनी कहानी मौजूद है कि कैसे खालिस्तान, एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन के बीज राजनीतिक प्रतिष्ठान के करीबी लोगों द्वारा बोए और पोषित किए गए थे। ये शक्ति, महत्वाकांक्षा और विश्वासघाती गठबंधन की कहानी है जिसके कारण राजनीतिक लाभ के लिए करिश्माई उपदेशक से उग्रवादी नेता बने जरनैल सिंह भिंडरावाले की भर्ती की गई। जैसा कि देश ने देखा, भारत की राजनीतिक दिग्गज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अनजाने में उस नेता को पाला-पोसा जो अंतत: 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या का कारण बना।

उस अशांत समय के निशान आज भी राष्ट्र की सामूहिक स्मृति को परेशान करते हैं। दुनिया अक्सर खालिस्तानी खतरे की सीमा से बेखबर रही और इसे भारत-केंद्रित समस्या के रूप में ही देखा गया। हालांकि यह भ्रम 1985 में टोरंटो से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में हुए भीषण विस्फोट में टूट गया, जिसमें 329 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह एक डरावनी याद दिलाने वाली घटना जिसने पहली बार दुनिया को ये एहसास कराया कि खालिस्तानी आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। फिर भी, पश्चिम और अधिकांश हिस्सा इस खतरे की गंभीरता को समझने में विफल रहा। अब, वर्तमान समय में खालिस्तानी उग्रवाद का जिन्न एक बार फिर कनाडा में अपना सिर उठा रहा है, जहां अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने एक विवादास्पद खालिस्तान जनमत संग्रह का आयोजन किया, जिसने एक

सुलगते मुद्दे को फिर से जन्म दिया। ये आतंक की एक ऐसी कहानी है जिस पर दुनिया को गौर करने की दरकार है।

कनाडा में फिर हुआ जनमत संग्रह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के सामने थे। उन्होंने कनाडाई धरती पर बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की गहरी आशंकाओं को व्यक्त किया। यह ध्यान देने की अपील थी, जिसे तात्कालिकता की भावना के साथ प्रस्तुत किया गया था जो वर्षों से चल रही थी। इससे ठीक इतर सरे शहर के एक गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह हुआ, वही गुरुद्वारा जिसके प्रमुख एसएफजे का हरदीप सिंह निज्जर था, जिसकी 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा सरकार के प्रति भारत की बार-बार की गई चिंता एक चेतावनी की तरह है, जो अलगाववादी गतिविधियों के लिए कनाडाई क्षेत्र के दुरुपयोग के खिलाफ सतर्कता की एक हताश अपील है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट होता गया कि तत्काल कार्रवाई एक मायावी सपना है।

प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेते हुए, भारत की दलीलों का जवाब देने में अनिच्छा की तस्वीर पेश की। खालिस्तानी उग्रवाद का जिन्न कायम रहा, एक भयावह उपस्थिति जो कूटनीति के बंधन और राष्ट्रों के संकल्प की परीक्षा लेती रही। 20 मार्च 2023 को भी दुनिया ने अराजकता और विनाश का बेशर्म तमाशा देखा, जब खालिस्तानी कट्टरपंथियों की भीड़ ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अपना गुस्सा निकाला। बमुश्किल एक दिन बाद, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास भी इसी तरह के हमले का शिकार हो गया। तब वाशिंगटन में भारतीय दूतावास पर आतंक का साया मंडरा रहा था, लेकिन हमारी सतर्क गुप्त सेवाओं ने इस नापाक साजिश को विफल कर दिया। ये चौंकाने वाली घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि पुनर्जीवित खालिस्तान आंदोलन अब कोई दूर की, भारत-केंद्रित चिंता नहीं है यह एक विषैला सांप है जो कनाडा के केंद्र में लिपटा हुआ है। इस कट्टरवाद का केंद्र, अलगाववाद का यह संभावित टिंडरबॉक्स, पंजाब नहीं है, यह कनाडा है।

ग्लोबल दस्तक देता ये खतरा

दुनिया इस खतरनाक वास्तविकता से आंखें मूंदने का जोखिम नहीं उठा सकती। प्रधान मंत्री ट्रूडो, अब हम पर विश्वास करने का समय आ गया है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो खालिस्तानी उग्रवाद की लपटें भारत को नहीं, बल्कि कनाडा को अपनी चपेट में ले सकती हैं। खतरा वास्तविक है और यह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।

गृह मंत्री साहू के मुख्य आतिथ्य में सम्भाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आगाज

2 हजार 686 प्रतिभागी खिलाड़ी संभागीय प्रतियोगिता में ले रहे हैं भाग

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 17 जुलाई हरियाली त्यौहार से ग्राम पंचायत स्तर से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का प्रारंभ किया गया है। आज संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ दुर्ग जिले के ग्राम पुरई स्कूल प्रांगण में हुआ।

इस तीन दिवसीय आयोजन में संभाग के दुर्ग, राजनांदगॉव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मानपुर-मोहला अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ सहसपुर गंदई जिला के 2 हजार 686 प्रतिभागी खिलाड़ी संभागीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जिसमें गिल्ली- डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़ (लंगरची), कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी, बिल्स, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बीकूद , कुश्ती एवं रस्सीकूद शामिल है। इन खेलों में तीन आयु वर्ग 0-18, 18-40

एवं 40. महिला/ पुरूष आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे।

शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री श्री साहू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री श्री भुपेश बघेल का कहना है कि सर्वहारा वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर विकास के पैमाने तय करना है। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर राज्य सरकार अधोसंरचनात्मक विकास के साथ यहां के संस्कृति को पूर्नजीवित करने और पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से पारंपरिक खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री श्री साहू ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल अन्य जिलों के खिलाड़ियों को अवगत कराया कि दुर्ग जिले के पुरई को खेलगांव के नाम से जाना जाता है। यहां की खेल प्रतिभाओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पुरई के खिलाड़ियों की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां पर खेल अकादमी बनाने की सहमति दी है। गृहमंत्री श्री साहू ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभारंभ अवसर पर संभागायुक्त श्री जे.पी. पाठक ने स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने आयोजन के उद्देश्यों को रेखांकित किया। नगर निगम भिलाई -चरौदा के महापौर श्री निर्मल कोसरे ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना से खेलने की अपील की। इस अवसर पर नगर निगम रिसाली की महापौर श्रीमती शशि सिन्हा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा और खेल विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण एवं प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित थे।

रायगढ़ में महापौर अमृत जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा

रायगढ़। रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी की तरफ से अमृत जानकी काटजू महापौर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। रायगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने यह अविश्वास प्रस्ताव को लाने का काम किया था। 31 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिस पर 15 सितंबर को चर्चा होनी थी। लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। जिससे यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया।

बीजेपी ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर अमृत जानकी काटजू पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी में शहर में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि महापौर शहर के विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। जिसकी वजह से शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हो पाया है।

इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर स्वार्थ की राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी अपने कुनबे को एकजुट भी नहीं रख पाई है। बीजेपी के कुल 21 पार्षदों में सिर्फ 18 पार्षद ही आ सके। बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों को लेकर गलत आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पार्षदों में नाराजगी है। जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कर रायगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष पर संकुचित मानसिकता के तहत काम करने का आरोप लगाया है।

गोबर वाली सरकार कहकर भाजपा उड़ाते थे हंसी, आज कर रहे हैं तारीफ : लखनपाल

राज्य सरकार ने किया उल्लेखनीय कार्य, इसलिए लौटना हैं तय

बेमेतरा। राज्य सरकार ने जब से गोबर खरीदी की शुरआत की है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग गोबर वाली सरकार कहकर हंसी उड़ाते थे लेकिन आज वहीं लोग राज्य सरकार की इस योजना की तरीफ कर रहे है। कोरोना काल से लेकर अब तक राज्य सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया हैं इसलिए इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय हैं। उक्त बातें हिमाचल प्रदेश के प्रवासी विधायक और पर्यवेक्षक इंदरदत्त लखनपाल ने विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं। इस दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल, जावेद खान, अवनीश राघव, टीआर जनार्दन उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि आगामी दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि यहां की सरकार के द्वारा किए गए कार्य बेमिसाल है। पहले देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है जिसकी वजह से भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। कोरोना काल के बाद भी यहां की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है जिसकी वजह से सरकार का लौटना तय है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं, युवाओं एवं किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। केंद्र सरकार के असहयोगात्मक रवैया के बावजूद भी सरकार ने जो कार्य किए हैं यह उल्लेखनीय है।

लखनपाल ने कहा कि भाजपा के लोग गोबर वाली सरकार कह कर हंसी उड़ाते थे और तंज कसते थे, अब भाजपा नेता और आरएसएस के लोग इस योजना की सराहना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बनाई गई गोबर खरीदी योजना की नीति की चारों ओर तारीफे हो रही है। जो लोग तंज कसकर मजाक उड़ाते थे आज उन्हीं के नेता अपने प्रदेश में इस योजना को लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन ने उन्हें दुर्ग लोकसभा का पर्यवेक्षक बनाया है। क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं व संगठन के लोगों से बूथ स्तर में जाकर मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के दौरान पाई गई कमियों को दुरुस्त करने पार्टी संगठन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

महिला समूहों के बनाए गणेश प्रतिमा बिराजेंगे पंडालों पर

महासमुंद। छत्तीसगढ़ की महिलाएं रीपा योजना से पहले खेत खलिहान और मिट्टी से जुड़े कामकाज करती थी। माटी कला को निखारे के लिए पर्याप्त संसाधन और आय का जरिया नहीं था, लेकिन अब रीपा योजना आने के बाद महिलाएं सशक्त हो गई हैं। इस योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों ने अपने हुनर और मेहनत से एक नई पहचान बनाई है। कई प्रकार के निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में महासमुंद जिले के मां चन्द्रहसिनी महिला समूह गणेश चतुर्थी का त्यौहार के अवसर पर गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं। महिला स्व सहायता समूहों ने एलईडी बल्ब का निर्माण, फेंसिंग तार जाली का निर्माण, फ्लाई ऐस ईंट या गोबर पेंट का निर्माण या खाद्य सामग्री का निर्माण का काम कर रही हैं। इसी प्रकार कई कामों को कर रही है, इससे उनका आर्थिक स्थिति भी बदल रहा है। हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर महिला समूह ने कम कीमत पर आकर्षक राखियां बनाकर अपने हुनर से सबको परिचित कराया था। इस बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर महासमुंद जिले में समूह की महिलाओं ने गणेश प्रतिमा का निर्माण किया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क गोड़बहाल से जुड़कर मां चन्द्रहसिनी महिला समूह की दीदियां कई आकार और रंगो की आकर्षक गणेश प्रतिमा का निर्माण कर रही हैं। ये महिला समूह पहले माटी कला कार्य से जुड़कर कार्य कर रही थीं। अब रीपा योजना आने पर इन्हें ज्यादा संसाधन और अवसर मिला। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत गोडबहाल गौठान से जुड़ी रीपा योजनांतर्गत चंद्रहासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं गणेश प्रतिमा का निर्माण कर रही हैं। इस बार महिला समूह की ओर से बने गए गणपति घरों और जगह-जगह पंडालों में विराजेंगे।

बालोद में कब्जे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण

- सराफा व्यवसायी पर आरोप, प्रशासन ने खत्म कराई हड़ताल

बालोद। बालोद जिले के ग्राम पंचायत झलमला के शासकीय जमीन में रसूखदार द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की मांग लेकर आज झलमला के ग्रामीण एवं युवा कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से पूरे गांव को बंद कर भूख हड़ताल किया गया। अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच लंबे समय तक वार्ता चली जहां पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और चक्का जाम करने निकले थे। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और द्विपक्षीय वार्ता के बाद हड़ताल खत्म किया गया। दरअसल पूरे ग्रामीण बालोद शहर के सर्राफा व्यवसायी विकास श्रीमाल पर कब्जे का आरोप लंबे समय से लगा रहे हैं।

ग्राम पंचायत झलमला में शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर बालोद युवा कांग्रेस और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साजन पटेल ने बताया कि ग्राम झलमला में खसरा क्रमांक 1233/1 रकबा 0.48 हेक्टेयर लगभग डेढ़ एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा करके प्रसन्ना वाटिका बनाकर आधिपत्य कर लिया गया है। जिसके खिलाफ लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जांच में कब्जा पाए जाने के बाद भी अतिक्रमण को खाली नहीं करवाया जा रहा है जिससे नाराज होकर हम सब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे प्रशासन से लंबी बातचीत हुई जहां प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कल भी आकर जमीन की माप करेंगे और पुन: कब्जाधारी को नोटिस देकर कब्जा खाली करवाया जाएगा इसके बाद हमने यह हड़ताल कुछ समय के लिए खत्म कर दिया है। ग्राम झलमला के सरपंच उमा पटेल ने बताया कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1233/1 में स्थित 0.4800 हेक्टर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। शासकीय रिकार्ड में यह जमीन घास मद में दर्ज है। अवैध कब्जे की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच की है। जांच में शिकायत को सही पाया गया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के बाद मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। राजस्व अमले की लापरवाही की वजह से शासन की कीमती जमीन पर आज भी अतिक्रमण है बार बार राजस्व अमला जांच और कार्रवाई की बात करती है पर कब्जा आज भी बरकरार है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची कांकेर

कांकेर। भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को कांकेर पहुंची है। कांकेर पहुंचने पर युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली के माध्यम से परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए आमसभा स्थल लाया गया। सभा स्थल में परिवर्तन यात्रा के कांकेर के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, विधायक शिवरतन शर्मा, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, विधायक रंजना साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाटिया, सांसद मोहन मण्डावी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर सभा शुरू की गई। आमसभा को सम्बोधित करते प्रेम प्रकाश पांडेय ने सरकार पर प्रहार करते कहा कि प्रदेश की भ्रष्ट, घोटालेबाज कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। भारी बारिश के बीच भी ये उमड़ी भीड़ बताती है कि कांग्रेस के सरकार से जाने का वक्त आ चुका है। झूठे वादों के बुनियाद पर खड़ी ये भूपेश बघेल की सरकार अब दोबारा आने वाली नहीं है। इस सरकार से युवा, किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, आम जनता खुश नहीं है।

जान जोखिम में डालकर कोटरी नदी पार कर रहे लोग

कांकेर। कांकेर जिले के छोटेबेटिया के तहत बेचाघाट में कोटरी नदी उफान पर है। लगातार सात दिनों से हो रही अनवरत बारिश से कोटरी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उफनते कोटरी नदी को ग्रामीण जान जोखिम में डाल कर नाव के सहारे पार करने का वीडियो भी समाने आया है। नदी का जल स्तर बढ़ने से लगभग एक दर्जन गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। जिले के परलकोट क्षेत्र में पखांजूर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सीतरम, बेचाघाट, राजामुंडा, बिनागुण्डा, मेसपी, केंगल, मेसपी जैसे दर्जनों गांव कोटरी नदी के उस पार बसें है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मियों के चार से पांच महीनों में कोटरी नदी में जल स्तर कम रहता है। लेकिन बारिश के शुरू से लेकर ठंड के आठ महीनों तक इन ग्रामीणों को रोजमर्रा के सामान, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं एवं शासकीय योजनाओं से संबंधित कामकाज के लिए उफनती हुई कोटरी नदी में जान जोखिम में डाल कर नाव से नदी को पार कर छोटेबेठिया बाजार और पखांजूर स्थित शासकीय कार्यालय में आना पड़ता हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों में अवकाश घोषित करने निर्देश

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बीते दो दिन से बारिश का दौर जारी है। स्थिति ऐसी है कि नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात हैं। कवर्धा की जीवनदायिनी नदी सकरी रौद्र रूप ले ली है। नदी किनारे बसे कई वार्डों में पानी घुस गया है। इस मानसून पूरे जिले में अब तक 811.5 मिमी बारिश हो चुकी है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कबीरधाम जिले में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होते तक जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर सभी संस्था प्रमुख को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि किसी विद्यालय में बारिश के कारण पानी भर जाने के कारण बच्चों को बैठाने में या स्कूल आने में समस्या आ रही हो अथवा नदी नालों में पानी होने के कारण स्कूल के आवागमन में समस्या हो तो पानी के निकास होने तक विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाए। किसी भी स्थिति में बच्चों को संकट में न डालें। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

दीपका खदान में बिजली गिरने से दो वाहनों के उड़े परखच्चे

कोरबा। कोरबा में दीपका खदान में आकाशीय बिजली गिरने से दो डंपरों के टायर सहित ग्लास के परखच्चे उड़ गए। वहीं पास में ही खड़ा कैंपर वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक डंपर का टायर फटने से कैंपर वाहन उसकी चपेट में आ गया। प्रदेश के साथ ही कोरबा में लगातार हो रही बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने का दौर जारी है। एसईसीएल की दीपका खदान के भीतर खड़े वाहनों पर बिजली गिरी। दीपका एक्सपेंशन के डंपर यार्ड में खड़े वाहनों पर आकाशीय बिजली गिरने से प्रबंधन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई।

घर में सो रहे मासूम बच्चे को करैत सांप ने डसा

जगदलपुर। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के ग्राम नैनमुर में रहने वाले एक छह वर्षीय मासूम बच्चे को एक करैत सांप ने डस लिया, बच्चे को सही समय में उपचार के लिए मेकाज लेकर परिजन तो निकले, लेकिन उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई, बच्चे के परिजनों ने सांप को पकड़कर घर में रखे हुए है, बच्चे की मौत के साथ ही घर में मातम छा गया। मामले के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि परपा थाना क्षेत्र के ग्राम नैनमूर में रहने वाले साधुराम के छह वर्षीय बेटा दिनेश अपनी मां बसंती के साथ पलंग पर सो रहा था कि अचानक से एक करैत सांप ने बच्चे की कमर में डस लिया। जिसके बाद बच्चे ने शोर मचाया, बच्चे की मां ने इसकी जानकारी पति के साथ ही घर वालों को दी। जहां परिजनों ने सबसे पहले सांप को पकड़कर उसे डिब्बे में भरने के साथ ही बच्चे को 112 डायल में लेकर मेकाज पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बच्चे की मौत हो गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन पर होगी अर्थदण्ड एवं सजा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए अवैध उत्खनन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर खान और खनिज अधिनियम के तहत अर्थदण्ड एवं कारावास की सजा होगी।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करते पाए जाने पर खान और खनिज अधिनियम (विकास और विनियमन) 1957 की धारा 21 (1) एवं 21 (2) के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके अनुसार अधिकतम दण्ड 5 वर्ष अथवा 2 वर्ष का कारावास एवं पाँच लाख रुपये का अर्थदंड और प्रत्येक दिन के लिए अर्थदण्ड

50 हजार रुपये प्रावधानित है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त आदतन व्यक्तियों द्वारा पुन: अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण किये जाने पर प्रकरण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं गंभीर प्रकृति के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के अपराध प्रकाश में आने पर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत की जायेगी।

हाथी विचरण की सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाने हाथी अलर्ट ऐप का किया जा रहा उपयोग

गौरेला पेंड्रा मरवाही। राज्य शासन द्वारा वनांचल क्षेत्रों में हाथियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने और जान-माल की क्षति पहुंचाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा हाथी विचरण की सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाने ''हाथी अलर्ट ऐप'' का उपयोग किया जा रहा है। मरवाही वन मंडल में नव पदस्थ वन मण्डलाधिकारी श्री शशि कुमार ने बताया कि हाथी एवं मानव संघर्ष के नियंत्रण तथा एनीमल अलर्ट एप्लीकेशन का उपयोग करने वन विभाग के अमले को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक विचरण की सूचना का पहुंचाना और जनहानि पर अंकुश लगाना है।

वन मण्डलाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पशु ट्रैकर और अलर्ट ऐप के जरिए हाथियों की गतिविधियों का विवरण (स्थान, झुंड, तिथि, व्यवहार, आदि) संबंधित हाथी मित्र दल (हाथी देखने वाले) द्वारा ओपन सोर्स ऐप पर दर्ज किया जाता है जो ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। हाथियों के स्थान के आधार पर एआई का उपयोग करके हाथी के स्थान के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित ग्रामीणों को वास्तविक समय के आधार पर कॉल एसएमएस, बजर अलर्ट भेजे जाते है। ऐप उपयोगकर्ता किसी भी समयावधि में हाथियों के झुंड की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं, जो पर्यावास सुधार कार्यों की योजना बनाने और मानव-हाथी संघर्ष को रोकने में सहायक है।

चुनाव से पहले सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई वाहन चेकिंग में 17 लाख कैश बरामद

सरगुजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान अंबिकापुर और सरगुजा में पुलिस की पेट्रोलिंग से लेकर सुरक्षा से जुड़े अभियान में तेजी आई है।

सरगुजा पुलिस शहर के कई इलाकों में नाकेबंदी कर दूसरे जिले से आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रही है।वाहन चेकिंग के दौरान 17 लाख कैश बरामद- सरगुजा पुलिस ने गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान 17 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। यह पैसा अंबिकापुर से एक कार सवार कोरबा लेकर जा रहा था। एनएच 130 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन रुपयों को बरामद किया है। चुनाव के मद्देनजर सरगुजा एसपी ने जिले भर में वाहन चेकिंग के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी चेकिंग के दौरान यह कर्रवाई की गई है।

डीएसपी ग्रामीण अखिलेश कौशिक ने कहा चुनाव के मद्देनजर अम्बिकापुर शहर और सरगुजा जिले से गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर चेकिंग प्वाइंट बनाया गया था। जिससे कैश बाहर ना ले जाया जा सके। इसी क्रम में कल उदयपुर में एक कार में 17 लाख कैश बरामद किए गए हैं। कार सवार ने कैश के संबंध में कुछ दस्तावेज दिखाए गए थे। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होने के कारण कैश जब्त कर लिया गया है। कार चालक ने बताया कि वो सूराजपुर जिले के लटोरी से कोरबा के कुसमुंडा जा रहे थे।अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

वाहन सवार ने कैश से जुड़े दस्तावेज नहीं किए पेश- कार चेकिंग के दौरान वाहन सवार ने इतनी भारी रकम से जुड़े कागजात पेश नहीं किए। कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाने पर पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है। सरगुजा की उदयपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नगद रकम को जब्त करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा पार्षद पुष्पा निरंजन साहू ने थामा कांग्रेस का हाथ

रायगढ़। जिले में कांग्रेस के लिए आज का

दिन काफी अच्छा रहा। एक तरफ वार्ड क्रमांक 34 की भाजपा पार्षद पुष्पा निरंजन साहू ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो दूसरी तरफ निगम मेयर के खिलाफ भाजपा की नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने पुष्पा निरंजन साहू ने कांग्रेस प्रवेश किया। निगम में भाजपा पार्षद मंडल की तरफ से महापौर जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। बीजेपी के 21 पार्षदों का भी साथ नहीं मिला। बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी रायगढ़ दौरे पर पहुंचे थे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली के जरिए छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। प्रदेश की जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालकर सरकार बनाने की अपील की, लेकिन उनके दौरे के दूसरे ही दिन भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो भाजपा में हुए शामिल

जशपुर। कुछ समय पहले ही भारतीय सेना से वीआरएस लेकर राजनीति में सक्रिय हुए पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। शामिल होने से पूर्व टोप्पो सैकड़ों गाडियों का काफिला लेकर अंबिकापुर से जशपुर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वे सीतापुर विधानसभा सीट से मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। टोप्पो सरगुजा जिले के मैनपाठ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोटछाल के रहने वाले हैं।

कांग्रेस के राज्य महिला सम्मेलन में शामिल होंगी 21 को प्रियंका गांधी

रायपुर। भिलाई में 21 सितंबर को आयोजित

कांग्रेस के राज्य महिला सम्मेलन कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। इस दौरान प्रियंका कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का प्रचार-प्रचार करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ कुछ और राष्ट्रीय स्तर के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिलाई पहुंच रहे है।

तीजा-पोरा तिहार महोत्सव में महिलाओं के साथ थिरके महापौर ढेबर

रायपुर। सुभाष स्टेडियम में महापौर एजाज ढेबर के द्वारा तीजा-पोरा तिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी और महिलाओं के बीच महापौर ढेबर सपत्निक थिरके। महापौर एजाज ढेबर ने इस अवसर पर महिलाओं को साड़ी व श्रृंगार का सामान देकर सम्मान किया। महापौर ने इस अवसर पर सभी महिलाओं के जीवन में खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि तीजा - पोरा तिहार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व का विषय है और यह छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीजा-पोरा तिहार में छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने परिवार के साथ आगंतुकों को आत्मसमर्पण और समर्पण का संदेश देती हैं।

आई.टी.आई. में छात्रावास अधीक्षक पद के दस्तावेज सत्यापन का आज अंतिम अवसर

रायपुर। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को 15 सितम्बर 2023 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सेजबहार, रायपुर में तक आयोजित किया गया है। जो अभ्यर्थी उक्त तिथि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे 16 सितम्बर 2023 को उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट http://cgiti.cgstate.gov.in/ तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी उसी दिवस सायं 5 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा/आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के मेघावी बच्चों को मिलेगा छात्रवृत्ति योजना का लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के मेघावी बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे जो कक्षा छठवी से बारहवीं तक 71 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स इस योजना के लाभ ले सकेंगे। वहीं स्नातक की डिग्री करने वाले विद्यार्थी जो 60 प्रतिशत से अधिक अंक ले हैं वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि रायपुर संभाग के भूतपूर्व सैनिकों का पंजीयन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर में करा चुका हैं, वे अपने बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने धान खरीदी की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के

कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्र्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए।

खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली। बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढ़े छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव के विरूद्ध नान में चावल जमा करने की समीक्षा की गई। जिन जिलों का अभी तक चावल जमा करना शेष है उन्हें तत्काल जमा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाओं के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिवएन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

नैसर्गिक कोसा से दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार के निर्देशन में विगत पौने पांच साल में रेशम प्रभाग ने दो लाख से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। रेशम प्रभाग में संचालित नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम अंतर्गत 2 लाख 5 हजार 565 लोगों को नियमित रोजगार मिला है। इस योजना अंतर्गत 6386.56 लाख नग नैसर्गिक टसर का ककून का उत्पादन किया गया है। जिससे एक लाख 9 हजार 856 अनुसूचित जनजाति और 19 हजार 196 अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार मिला है। राज्य के दंतेवाड़ा, जगदलपुर (बस्तर), उत्तर बस्तर के तहत कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर तथा धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, कोरबा, जशपुर, कोरिया जिला वनों से आच्छादित क्षेत्र है। इन सभी जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते है जो कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े गए हैं। इन लोगों को शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर रेशम पालन को कृषि का दर्जा मिला है। इससे रेशम पालन को बढ़ावा मिलेगा। वनांचल के सभी जिलों में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री के कबूलनामे से यह सत्य सामने आ गया है कि बघेल झूठ का निर्माण करते हैं : मूणत

■ कांग्रेस के संचार प्रमुख ने प्रधानमंत्री का दौरा रद्द बताकर मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर कांग्रेस अफवाह फैला रही थी, मोदी के उसी दौरे में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस का झूठ बेनकाब करते हुए कहा है कि मोदी ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं और भरोसा है कि आगे भी देते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने सबके सामने स्पष्ट किया है कि मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया। इससे यह आईने की तरह साफ हो गया है कि उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को छोड़कर पूरी कांग्रेस झूठ बोलती है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है। राज्य शासन की ओर से उप मुख्यमंत्री के कबूलनामे से सत्य सामने आ गया है कि भूपेश बघेल झूठ का निर्माण करते हैं और कांग्रेसियों को उस झूठ का सेल्समैन बना दिया है।भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त कहीं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। यह कांग्रेस का तुच्छ आचरण और अक्षम्य अपराध है। यह कांग्रेस की कुंठित और निचले स्तर की मानसिकता को दर्शा रहा है। कांग्रेस का यह कृत्य कांग्रेस में मची हार की दहशत को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर कार्यक्रम को लेकर भी कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने की नाकाम कोशिश की थी। एक राजनीतिक दल ऑफिशियल बयान देकर भ्रम फैलाने का काम करे, इससे अधिक शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। कांग्रेस ऊटपटांग हरकतें करने से बाज नहीं आ रही। यह उनके मुख्यमंत्री के निर्देशन में हो रहा है, जो मानसिक दिवालिएपन का परिचायक है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के मीडिया

प्रमुख ने वीडियो बयान जारी कर प्रधानमंत्री के निश्चित कार्यक्रम के बारे में भ्रम फैलाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने यह भी झूठ फैलाया कि रायगढ़ के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटने के कारण प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। जबकि, जब यह बयान जारी किया जा रहा था, तब सभा-स्थल पर 1 लाख से अधिक का जनसमूह एकत्रित था। हजारों की संख्या में सारंगढ़ से रायगढ़ मार्ग पर लोग यातायात में फँसे थे और कांग्रेस ने इससे घबराकर झूठा प्रचार करने की घटिया हरकत की। श्री मूणत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैण्डल से वर्षो पुराना एक वीडियो जारी कर यह बताने का प्रयास किया कि परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दो वर्ष पहले यह वीडियो बनाने का षडयंत्र कांग्रेस ने ही उत्तरप्रदेश के एक कार्यक्रम के दौरान किया था।

भारतीय जनता पार्टी के विधि विभाग कांग्रेस के इन झूठे प्रचारों को लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और थाना प्रभारी (सिविल लाइंस) के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा न्यायोचित कार्रवाई की मांग करेगी। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ,निर्वाचन समिति देख रहे, डॉ विजय शंकर मिश्रा और विधिक समिति देख रहे श्री जेपी चंद्रवंशी शामिल रहे।

डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कांग्रेस को दिखाया आईना : सरोज पांडेय

सिंहदेव बोले: मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया, मंच से की पीएम की तारीफ

रायपुर। पीएम नरेंद्र मोदी रायगढ़ के कोड़ातराई से दिल्ली जा चुके हैं। इसके बाद से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। जमकर सियासत हो रही है। दरअसल, मंच पर जब प्रधानमंत्री बैठे थे तब प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मंच पर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पीएम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके इस बयान से छत्तीसगढ़ बीजेपी को बना बनाया मौका मिल गया। राज्यसभा और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद सरोज पांडेय ने सिंहदेव के बयान के बहाने राज्य की भूपेश सरकार को घेरा है।

पीएम की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदवे ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ धरती पर प्रधानमंत्री की अगवानी करने का अवसर मिला। सर का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज देते रहे हैं और दे रहे हैं। भविष्य में भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रेल कॉरिडोर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकलसेल नागरिकों को उनकी बेहतर उपचार के लिए कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आप ने अपनी उपस्थिति से गति दी है। हमारे संविधान के व्यवस्था अनुसार केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। मैं यह कहने से भी नहीं चुकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य ने काम किया और कुछ मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी की तरह। केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। (इतना सुनते हुए पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए) मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश-प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

सरोज पांडेय ने राज्य सरकार को घेरा

सिंहदेव के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने राज्य सरकार को घेरते हुए निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूछा कि टीएस सिंहदेव सच बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं- अब यहां टीएस सिंहदेव सच बोल रहे हैं या भूपेश बघेल झूठ बोलते आ रहे हैं, क्योंकि जिस मुखरता के साथ सिंहदेव ने इंडी एलायंस के नेताओं को आईना दिखाया है जो लगातार यह कहते आ रहे हैं कि विपक्ष की सरकार जहां भी है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्रम मोदी का सौतेला व्यवहार रहता है।

अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आयोग के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आयोग के पदाधिकारियों और अधिकारियों की बैठक लेकर आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित योजना भवन में आज आयोजित बैठक में आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की राज्य में नियमित निगरानी में सहायता के लिए विकसित किए गए फ्रेमवर्क और एसडीजी डैशबोर्ड की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान तथा गोधन न्याय योजना की इवैल्युवेशन रिपोर्ट का विमोचन भी किया। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बैठक में बताया कि एसडीजी के लक्ष्यों को हासिल करने में शासकीय विभागों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की सहायता के लिए आयोग द्वारा प्रभावी फ्रेमवर्क व डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति के मूल्यांकन के लिए ''एसडीजी स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क'' तथा जिला स्तर पर मूल्यांकन के लिए ''एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क'' एवं उन पर आधारित प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई इवैल्युवेशन रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं के अनुसार संबंधित विभाग अपनी योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. टेकाम ने बताया कि ''एसडीजी डैशबोर्ड'' में सतत विकास लक्ष्य में वर्षवार लक्ष्य आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण है।

नवाचार, रचनात्मकता और आजीवन सीखने की भावना होनी चाहिए विद्यार्थियों में : राज्यपाल

रायपुर। शिक्षा एक आजीवन यात्रा है और सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और आजीवन सीखने की भावना होनी चाहिए। विद्यार्थी अपने कौशल को लगातार बढ़ाने, अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और अपने संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति से अवगत रहने के अवसरों की तलाश करें। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज आई.टी.एम. विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में यह उद्गार व्यक्त किए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित आई.टी.एम. विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 13 गोल्ड मेडल सहित 377 उपाधियां वितरित की गई। केन्द्रीय भंडार के सीईओ और एमडी श्री मुकेश कुमार, आई.टी.एम के प्रोफेसर

आर.एस.एस मनी और कर्नाटक संगीत विशेषज्ञ श्रीमती जी. शारदा सुब्रमण्यम को विश्वविद्यालय की मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिचंदन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि यह दीक्षांत समारोह न केवल विद्यार्थियों की सफलता का उत्सव है, बल्कि प्रत्येक के अंदर मौजूद अपार संभावनाओं का भी परिचायक है। शिक्षा सदैव सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति रही है। इसमे बाधाओं को तोडने, मानदंडों को चुनौती देने और अवसर पैदा करने की शक्ति है। विश्वविद्यालय की शिक्षा यात्रा आपके भविष्य को आकार देगा, आपके द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए होगा।

श्री हरिचंदन ने कहा कि हम एक तेज और गतिशील दुनिया में रह रहे हैं, जहां तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण, उद्योगों और व्यवसायों को नया आकार दे रहा है। अपने चुने हुए क्षेत्रों में प्रासंगिक बने रहने और आगे बढने के लिए इन परिवर्तनों को अपनाना आवश्यक है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों के उत्थान के लिए भी करें। जिम्मेदार नागरिक बनें और हमारे महान राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दें।

सारंगढ़ विधानसभा में पांच साल में जनता बदल देती है अपना नेता

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आज हम बात करेंगे सारंगढ़ विधानसभा की। जो अब नए जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आता है। इस विधानसभा में मौजूदा समय में कांग्रेस का कब्जा है।उत्तरी गणपत जांगड़े ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी। इस दौरान उत्तरी जांगड़े को बरमकेला क्षेत्र से बड़ी बढ़त मिली थी। अगर सारंगढ़ विधानसभा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो यहां कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। पांच साल में होने वाले चुनाव में जनता अपना नेता बदलती रही है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनने से पहले सारंगढ़ सीट रायगढ़ जिले में आती थी। मौजूदा समय में सारंगढ़ बिलाईगढ़ का तीसवां जिला बन चुका है।साल 2021 15 अगस्त के दिन सीएम भूपेश बघेल ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा किया थी। इसके दो महीने बाद 20 अक्टूबर 2022 को राजपत्र में इस जिले को शामिल करने की आधिकारिक घोषणा हुई।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 498196 हैं। जिसमें पुरुषों की संख्या 249439 और महिला मतदाता 248748 हैं। तृतीय लिंग के 9 मतदाता, डाकसेवा मतदाता 297, युवा मतदाता 12428, दिव्यांग मतदाता 7131 हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 59 मतदाता रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के केंद्र में वोट डालेंगे।

समस्याएं और मुद्दे

सारंगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र का रेवेन्यू जेनरेट करने का मुख्य स्रोत स्टोन क्रशर खदानें हैं। यहां के ट्रिमरलगा गांव से कई दर्जन गिट्टी खदान हैं। जहां से सारंगढ़ के साथ ही साथ रायगढ़, ओड़िसा में पत्थर सप्लाई किए जाते हैं। सारंगढ़ के व्यापारी ज्यादातर खरीदारी ओड़िसा से करते हैं। लिहाजा सड़कों में हैवी गाड़ियों का परिचालन होता है। जिसके कारण सड़कों की हालत खस्ता है।तालाबों का शहर कहे जाने वाले सारंगढ़ में तालाबों की हालत खस्ता है।बस स्टैंड में सुविधाओं की कमी है। सारंगढ़

बिलाईगढ़ को एक साथ जिला बनाने का विरोध हो रहा है।स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो अभी भी सारंगढ़ में काफी काम होना बाकी है।वहीं आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खुलने से भी स्थानीय लोग नाराज हैं।

2018 के नतीजे

विधानसभा 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हो गया। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में जीत हासिल की थी।जिसमें सारंगढ़ सीट से कांग्रेस के उत्तरी जांगड़े ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के केराबाई मनहर को 52389 वोट से मात दी थी।कांग्रेस के उत्तरी गनपत जांगड़े को 101834 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। बीजेपी से केराबाई मनहर को 49445 वोट मिला। बसपा के अरविंद कुमार को 31083 वोट हासिल किए।

2013 के नतीजे

2013 में केरा बाई मनहर भाजपा प्रत्याशी ने 81971 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरा स्थान कांग्रेस प्रत्याशी पदमा घनश्याम मनहर का रहा। बीजेपी की प्रत्याशी केराबाई मनहर 15844 मतो के अंतर से जीत दर्ज की थी।

सारंगढ़ विधानसभा का इतिहास

किसी जमाने में सारंगढ़ की राजनीति गिरिविलास पैलेस से संचालित होती थी। वक्त बदला और हालात बदले तो राज परिवार ने राजनीति से दूरी बना ली।जिसके बाद से इस सीट पर कभी भी राजपरिवार का दखल नहीं रहता है। इस सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था।इसके बाद बसपा ने साल 2003 और 2008 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर इसे बसपा का गढ़ बनाया।लेकिन साल 2013 में बीजेपी ने इस सीट पर परचम लहराया।वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस सीट पर जीती। अब देखना होगा 2023 में कौन यहां बाजी मारता है।

40 दिन की मोहलत पर एक सरकार

अमिताभ श्रीवास्तव

जालना जिले की अंबड़ तहसील के अंतरवाड़ी सराटी में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल का आमरण अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। मंगलवार रात को संवाद, बुधवार शाम कोशिश और गुरुवार सुबह सफलता से पहले 16 दिन तक महाराष्ट्र सरकार चैन से नहीं बैठ पा रही थी। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री और एक उपमुख्यमंत्री मराठा होने के बावजूद सरकार को न संकट का समाधान आसानी से मिल रहा था और न वह कुछ कहने की स्थिति में थी। अलबत्ता राज्य की मजबूत सरकार को एक दुबले-पतले ग्रामीण से निपटने में पूरे मंत्रिमंडल की ताकत लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा था। महाराष्ट्र के अतीत में देखा जाए तो मराठा आरक्षण का मुद्दा कभी नया नहीं रहा। अस्सी के दशक के आरंभ में माथाडी कामगार नेता अन्नासाहब पाटिल ने सबसे पहले इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 22 मार्च 1982 को अन्नासाहब पाटिल ने मुंबई में 11 अन्य मांगों के साथ मराठा आरक्षण के लिए पहला मार्च निकाला। उस दौरान बाबासाहब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सुनवाई कर आरक्षण के लिए सहमति जताई, लेकिन सरकार गिर जाने से बात आगे नहीं बढ़ी। बाद में कई आयोग और समिति गठित किए गए। वर्ष 1995 में पहले न्यायमूर्ति खत्री आयोग, फिर आरएम बापट आयोग और वर्ष 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की अध्यक्षता में समिति बनी। समिति ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को अपनी सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी, जिसे स्वीकार कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक विशेष प्रवर्ग तैयार किया गया। वर्ष 2014 में आरक्षण की घोषणा होने के तत्काल बाद उसे उच्च न्यायालय में चुनौती मिल गई। बाद में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने स्थगित कर दिया। वर्ष 2014 में नई सरकार आने के बाद वर्ष 2017 में फिर एक न्यायमूर्ति एस.बी। म्हसे के नेतृत्व में आयोग बना, लेकिन उनके निधन के बाद न्यायमूर्ति एमजी गायकवाड़ की नियुक्ति हुई। वर्ष 2018 में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई और उसी साल विधानसभा में उसे स्वीकार भी कर लिया गया। बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती मिलने पर गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों को कुछ परिवर्तन के साथ सहमति मिल गई। किंतु आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली तो वह वहां नहीं टिक सका और निरस्त हो गया। करीब चालीस साल से अधिक संघर्ष जो कई सरकारों, आयोगों और अदालत से सहमति पाकर देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा तो अंतिम मुकाम पर राज्य सरकार अदालत में अपना पक्ष रखने में कमजोर साबित हुई। कुल जमा वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कानून बनाकर मराठा समुदाय को दिए 13 प्रतिशत आरक्षण पर मई 2021 में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने रोक लगा दी। साथ ही कहा कि आरक्षण को लेकर 50 प्रतिशत की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता।

इंडी एलायंस ने आपातकाल की याद दिलाई

अजय सेतिया

इंडी एलायंस की को-ऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शरद पवार की अध्यक्षता में हुई। को-ऑर्डिनेशन कमेटी में वही सबसे सीनियर नेता हैं। जब कमेटी बनी थी, तब हैरानी हुई थी कि सोनिया, राहुल, खड़गे, लालू, नीतीश, ममता बनर्जी के बिना को-आर्डिनेशन कमेटी का क्या मतलब। लेकिन अब मतलब समझ में आ रहा है कि कोई कन्वीनर नहीं बनेगा। नीतीश कुमार को कन्वीनर और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जदयू की मांग दबा दी गई है।

कोऑर्डिनेशन कमेटी में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन सदस्य हैं, वे सब पहली मीटिंग में मौजूद भी थे। इस मीटिंग में चार बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए। इनमें से दो पर मुम्बई की मीटिंग में चर्चा हुई थी, लेकिन सहमति नहीं हुई थी। पहला फैसला यह हुआ है कि सीट शेयरिंग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगी। अरविन्द केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मुम्बई बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग की मांग रखी थी, हालांकि मीटिंग में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग की बात कह दी थी, लेकिन आधिकारिक फैसला नहीं हुआ था।

वैसे को-आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग से पहले ही कई राज्यों में सीट शेयरिंग पर आपसी चर्चा शुरू हो चुकी थी। जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में शुरुआती चर्चा के बाद बातचीत टूट चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी की दस में से चार सीटों की मांग ठुकरा कर कांग्रेस के सभी दस सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है, जबकि विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं।

हरियाणा पहला उदाहरण है कि सीट शेयरिंग पर इंडी एलायंस का सच से सामना हुआ है। इसीलिए केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग करने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि वह राष्ट्रीय पार्टी है, उसे सभी हिन्दी भाषी राज्यों में सीट चाहिए। केजरीवाल ने सभी राज्यों में

विधानसभाओं का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के चुनाव दूर होने के बावजूद उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की धमकी दे दी, जबकि मध्यप्रदेश में तो दस उम्मीदवारों का एलान भी कर दिया। अब देखना यह होगा कि इंडी एलायंस की अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में पहली रैली करने का जो दूसरा फैसला हुआ है, तब तक क्या होता है। क्या राहुल गांधी और केजरीवाल उस रैली में मध्यप्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने का एलान कर पाएंगे।

को-आर्डिनेशन कमेटी में सीट शेयरिंग और रैली के बाद तीसरा फैसला जातीय जनगणना की मांग उठाने का हुआ है। मुम्बई बैठक में इस मुद्दे पर गहरे मतभेद थे। लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को एलायंस के राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करने की मांग उठाई थी, जिसका ममता बनर्जी, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ने विरोध किया था। लालू यादव और नीतीश कुमार ने अपनी मांग छोड़ी नहीं थी, जिस पर ममता बनर्जी नाराज होकर प्रेस कांफ्रेंस से पहले ही चली गई थी। लालू यादव ने उनके प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं होने पर नाराजगी का इजहार भी किया था।

इस मीटिंग में जातीय जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करने से पहले पर्दे के पीछे मानमनोव्वल का लंबा सिलसिला चला। मुम्बई में जातीय जनगणना का विरोध करने वाले अरविन्द केजरीवाल ने राघव चड्ढा को और उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को मीटिंग में भेजा था, लेकिन ममता बनर्जी ने किसी को भी मीटिंग में नहीं भेजा। मीडिया के सवालों से बचने के लिए के.सी. वेणुगोपाल ने अपने बयान में पहले ही कह दिया कि ईडी के सम्मन के कारण अभिषेक बनर्जी मीटिंग में नहीं आ सके। ईडी ने उन्हें टीचर भर्ती घोटाले की पूछताछ के लिए सम्मन किया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अभिषेक बनर्जी को सम्मन भेजने के लिए ईडी और मोदी सरकार की आलोचना की।

सीट शेयरिंग, भोपाल रैली, जातीय जनगणना के बाद चौथा फैसला सब को आश्चर्यचकित कर देने वाला है। वह फैसला यह है कि गठबंधन के सभी दल उन न्यूज चैनलों के एंकरों की डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, जो इंडी एलायंस के दलों से टेढ़े सवाल पूछते हैं। या मोदी समर्थक राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं।

को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने मीडिया सब कमेटी को ऐसे एंकरों की लिस्ट बनाने को कहा है। इनमें सबसे पहला नाम रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी का आता है, जिनका पहले भी कांग्रेस ने लंबे समय तक बायकाट किया था। अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के बायकाट के कारण सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर अक्सर हमलावर रहते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के समय पालघर में दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या के बाद अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा था कि अगर किसी पादरी की इसी तरह पीट पीट कर हत्या हो जाती, तो क्या सोनिया गांधी तब भी चुप रहती। अर्नब गोस्वामी के सीधे सवालों के चलते कांग्रेस नेताओं ने देश भर में कई जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। मुम्बई में उनकी कार पर हमला भी हुआ था, फिर टीआरपी का एक केस बना कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी।

अर्नब गोस्वामी के बाद टाइम्स नाऊ नवभारत के एंकर सुशांत सिन्हा और आजतक के एंकर सुधीर चौधरी का नाम लेकर कहा गया कि ऐसे एंकरों की लिस्ट बनाई जाए, जिनके कार्यक्रमों का इंडी एलायंस के सभी दल बायकाट करेंगे। गुरूवार को लिस्ट जारी भी कर दी गई, जिसमें अदिति त्यागी (जी न्यूज), अमन चोपड़ा (न्यूज 18), अमिश देवगन (न्यूज 18), आनन्द नरसिम्हन (सीएनएन न्यूज 18), अशोक श्रीवास्तव (दूरदर्शन), चित्रा त्रिपाठी (आजतक), गौरव सांवत (इंडिया टुडे), नाविका कुमार (टाईम्स नाऊ), प्राची पराशर (इंडिया टीवी), रुबिका लियाकत (भारत 24), शिव अरूर (इंडिया टूडे) के नाम हैं।

इस तरह राजनीतिक नफरत की आंच अब मीडिया तक पहुंच गई है। गुजरात दंगों के बाद पूछे गए टेढ़े सवालों से झल्ला कर करण थापर के शो से तो नरेंद्र मोदी सिर्फ उठ कर गए थे। अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी के शो से तो समूचा विपक्ष उठकर चला गया।

अब तक तो सरकार को मीडिया से दिक्कत होती थी। वह मीडिया पर तरह तरह की पाबंदियां लगाती थी। मोदी सरकार को भी मीडिया से दिक्कत है। उसने भी संसद और सरकारी दफ्तरों में मीडिया के प्रवेश पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया के प्रति दुर्भावना है, क्योंकि दिल्ली के मीडिया ने भी गुजरात दंगों के समय एकतरफा और वह भी तथ्यहीन रिपोर्टिंग की थी। सालों तक दिल्ली के मीडिया ने उन पर आरोप लगाना जारी रखा था कि दंगे उनके इशारे पर ही हुए थे।

इसके बावजूद मोदी जब भी दिल्ली आते थे, किसी न किसी चैनल को इंटरव्यू देते थे। इंडिया टूडे कॉनक्लेव में तो दिग्विजय सिंह और फारूख अब्दुला को भी उनसे सवाल पूछने दिए गए थे। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल इस तरह पत्रकारों और एंकरों के शो का बायकाट करेंगे, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। अर्नब गोस्वामी का तो चलो खुद का टीवी चैनल है, लेकिन बाकी एंकरों का बायकाट क्या उन मीडिया घरानों पर उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव नहीं है। यह एक चेतावनी भी है कि उनकी सरकार आ गई, तो उन्हें कहीं नौकरी नहीं करने दी जाएगी। पत्रकारों की आज़ादी पर इतना बड़ा प्रहार तो आपातकाल में भी नहीं हुआ था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-7)

गतांक से आगे...

जब इस विश्व की आत्मा के रूप में अनुभूति की जाती है, तो वह भोज्य रूप हो जाता है तथा आत्मा रूप से अविनाशी ब्रह्म सतत उसका भक्षण करता रहता है। जिसका आभास हो जाने से यह विश्व भोज्य पदार्थरूप हो जाता है तथा वह जब आत्मस्वरूप ज्ञात हो जाता है, तो निश्चय ही वह ब्रह्म के द्वारा भक्षित होता है।

सत्ता का लक्षण ही अस्तित्व माना जाता है तथा ब्रह्म से सत्ता पृथक् नहीं होती। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं और न माया कोई वास्तविक वस्तु ही होती है। योग साधकगण माया की कल्पना अपनी अन्तरात्मा से ही करते हैं। वह ब्रह्मज्ञान से बाधित होती हुई उन (साधक गणों) को साक्षीरूप में प्रतिभासित होती है। इस प्रकार से जिस ज्ञानी साधक को ब्रह्म के ज्ञान-विज्ञान की सम्पन्नता की अनुभूति हो गई है, वह चाहे इस सम्पूर्ण विश्व का अपने समक्ष दर्शन करता रहे; किन्तु वह उसे अपने से अलग कभी नहीं मानता। ऐसी ही यह उपनिषद् (रहस्यात्मक ज्ञान) है।

यह उपनिषद् कृष्णयजुर्वेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। इस उपनिषद् का मूल प्रयोजन चित्त शुद्धि है, जिसके द्वारा ब्रह्मज्ञान सहज प्राप्य है। इस उपनिषद् में सर्वप्रथम %शारीर यज्ञ के विषय में स्पष्टीकरण देने की घोषणा तथा उसका प्रतिफल (सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है) वर्णित है। तत्पश्चात् बाह्य प्राणाग्निहोत्र का प्रयोग स्पष्ट किया गया है। तदुपरान्त शारीराग्नि दर्शन नामक अपर-ब्रह्मविद्या का स्वरूप विवेचित हुआ है। शारीरानि विद्या द्वारा शारीर यज्ञ का निरूपण अगले क्रम में है। अन्त में इस %प्राणाग्निहोत्र% विद्या के पठन-पाठन की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस उपनिषद् का अध्येता एक ही जन्म में चित्त शुद्धि तथा (परिणाम स्वरूप) मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसी के साथ उपनिषद् पूर्ण हो गई है।

अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे (प्राणाग्निहोत्रोपनिषद् के अन्तर्गत) अनसूक्त एवं शारीर यज्ञ की व्याख्या प्रारम्भ की जाती है। जिस पुरुष शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात् अग्निहोत्र के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है॥ 1 अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी पर (निर्मित की गई वेदिका पर) अन्न को रखकर तत्पश्चात् नीचे लिखे (या ओषधय: .....। या फलिनीर्या:। जीवला नघारिषां 1) इन तीन मंत्रों तथा जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित ऐसी ये समस्त ओषधियाँ बृहस्पति-प्रसूत (विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत) हैं, ये ओषधियाँ हमें रोगों-पापों से मुक्ति प्रदान करें

जो अन्न अनि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्राय: बचाकर रखा जाता है, उस कल्याणकारी अन्न को ईशानदेव दोषमुक्त बनाएँ, उन ईशानदेव भगवान् शिव को यह आहुति समर्पित है ॥7॥

मंत्र सं0 2 से 7 तक के मन्त्रों द्वारा अन्न का स्पर्श करके उसे अभिमन्त्रित करें। तदनन्तर हाथ में जल लेकर मंत्र क्र0 8 व 9 क्रमश: अन्तश्चरसि ज़् एवं आप: पुनन्तु इन दो मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर अन्न का प्रोक्षण करें- आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी हैं, वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। ब्रह्मपूत पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। **क्रमश:**

विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस

ललित गर्ग

विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओजोन परत के सुरक्षित ना होने से जनजीवन, प्रकृति, पर्यावरण और पशुओं के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहां तक कि पानी के नीचे का जीवन भी ओजोन की कमी के कारण नष्ट हो जाएगा। ओजोन परत के नष्ट होने एवं उसकी कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, सर्दियों की तुलना में अधिक गर्मी होती है, सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं और हिमखंड गलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ओजोन परत की कमी स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए खतरा है।

आज समग्र मनुष्य जाति ओजोन में छिद्र होने एवं उसके नष्ट होने से पर्यावरण के बढ़ते असंतुलन से संत्रस्त है। प्रकृति एवं पर्यावरण की तबाही से पूरा विश्व चिन्तित है। कहा नहीं जा सकता कि ओजोन सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये सोची गयी योजनाएं, नीतियां और निर्णय कब, कैसे सफल निष्पत्तियों तक पहुंचेंगी। इधर तेज रफ्तार से बढ़ती दुनिया की आबादी, तो दूसरी तरफ तीव्र गति से घट रहे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। समूचे प्राणि जगत के सामने अस्तित्व की सुरक्षा का महान संकट है। पिछले लम्बे समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ओजोन से जुड़ी हुई है। आज पृथ्वी विनाशकारी हासिए पर खड़ी है। सचमुच आदमी को जागना होगा। जागकर फिर

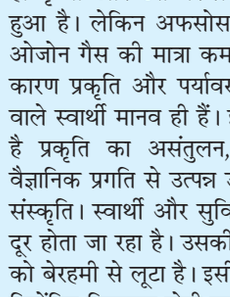

एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है। यह भटकाव ओजोन परत के लिये गंभीर खतरे का कारण बना है।

ओजोन गैस हमारी जीवन रक्षक है। ओजोन से ही पृथ्वी और उस पर प्रकृति एवं पर्यावरण टिका हुआ है। लेकिन अफसोस है, कि ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा कम हो रही है। इसका मुख्य कारण प्रकृति और पर्यावरण का अति दोहन करने वाले स्वार्थी मानव ही हैं। इस संकट का मूल कारण है प्रकृति का असंतुलन, औद्योगिक क्रांति एवं वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्न उपभोक्ता एवं सुविधावादी संस्कृति। स्वार्थी और सुविधाभोगी मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। उसकी लोभ की वृत्ति ने प्रकृति को बेरहमी से लूटा है। इसीलिए ओजोन की समस्या दिनोंदिन विकराल होती जा रही है। ओजोन परत का छेद दिनोंदिन बढ़ रहा है। सूरज की पराबैंगनी किरणें, मनुष्य शरीर में अनेक घातक व्याधियाँ उत्पन्न कर रही हैं। समूची पृथ्वी पर उनका विपरीत असर पड़ रहा है। जंगलों-पेड़ों की कटाई एवं परमाणु ऊर्जा के प्रयोग ने स्थिति को अधिक गंभीर बना दिया है। न हवा स्वच्छ है, न पानी, न मौसम का संतुलित क्रम। वैज्ञानिको ने ओजोन परत से जुड़े एक विश्लेषण में यह पाया है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोरिडे आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इन रसायन पदार्थों को 'ओजोन क्षरण पदार्थ' कहा गया है। इनका उपयोग हम मुख्यत: अपनी दैनिक सुख-सुविधाओ में करते हैं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि। ओजोन चिन्ता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि कहां खो गया वह आदमी जो संयम एवं सादगीपूर्ण प्रकृतिमय जीवन जीता था, जो स्वयं को कटवाकर भी वृक्षों को काटने से रोकता था? गोचरभूमि का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था। जिसके लिये जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी। कत्लखानों में कटती गायों की निरीह आहें जिसे बेचैन कर देती थी। जो वन्य पशु-पक्षियों को खदेड़कर अपनी बस्तियां बनाने का बौना स्वार्थ नहीं पालता था। अपने प्रति आदमी की असावधानी, उपेक्षा, संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना के कारण ही आज ओजोन क्षत-विक्षित हो रही है। ओजोन मनुष्य के द्वारा किये गये शोषण एवं उपेक्षा के कारण ही नष्ट हो रही है, और तभी बार-बार भूकम्प, चक्रावत, बाढ़, सुखा, अकाल, कोरोना महामारी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सुविधावादी जीवनशैली एवं बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ओजोन को भारी नुकसान हो रहा है। एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस फ्रियान-11, फ्रियान-12 भी ओजोन के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है क्योंकि इन गैसों का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने में सक्षम है।

चीन के हाथों से फिसलता जी-20

श्रीकांत कोंडापल्ली

दिल्ली में जी-20 बैठक के समाप्त होने के साथ चीन जरूर उस नयी वैश्विक व्यवस्था के बारे में सोच रहा होगा, जो उसके हाथ से फिसलती लग रही है। कोरोना के बाद की की दुनिया में भारत पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण की दीवारों के बीच, एक समावेशी और बहुपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन हमेशा से जी-20 के केंद्र में रहता रहा है। अपनी 19 ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था, 1980 से 2010 के बीच 10 प्रतिशत की विकास दर, और पिछले दशक में सात प्रतिशत से ज्यादा के विकास की बदौलत, चीन जी-20 में अपनी एक अहम उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। वह जी-20 के कई सदस्यों के सबसे बड़े व्यापार सहयोगियों में से एक है। पिछले दो दशकों में, चीन ने वैश्विक व्यापार, निवेश, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास जैसे मुद्दों पर जी-20 की चर्चाओं को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया था। चीन ने वर्ष 2016 में हांग्जू में जी-20 के सम्मेलन की मेजबानी की थी और अपनी नीतियों और हितों के पक्ष में आवाज उठायी थी। उसने वहां वित्तीय बाजारों में सुधार, व्यापार में उदारता, आधारभूत ढांचे में विकास जैसे मुद्दे उठाकर बड़ी मात्रा में पूंजी, तकनीक और बाजारों को आकर्षित किया था। लेकिन, लगता है उसकी इस शानदार कहानी में मोड़ आ रहा है और इस कहानी से उसे अब तक जो फायदे हुए अब उनका सिलसिला थम रहा है।

चीन की आर्थिक वृद्धि की दर पिछले वर्ष घटकर लगभग तीन प्रतिशत रह गयी। ऐसा कुछ उसकी घरेलू नीतियों की वजह से हुआ जिसके तहत निर्यात की जगह घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर दिया

गया और मेड इन चाइना 2025 के स्थान पर आयात को बढ़ावा दिया गया। कोरोना महामारी ने भी असर डाला, जिसका जन्म वुहान में हुआ था। उसके सबसे बड़े साझेदारों ने भी चीन में बाजार वाली अर्थव्यवस्था में कमी पर सवाल उठाने शुरू कर दिये जिसका विश्व व्यापार संगठन की संधियों में वादा किया गया था। साथ ही, उसकी सौम्य सुरक्षावादी नीतियों, गैर-शुल्क बाधाओं तथा मुद्रा कीमतों में छेड़छाड़ पर भी सवाल उठे। साथ ही अन्य भू-राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त कोरोना, यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका-चीन संबंधों में आते बदलाव, यूरोप के कारोबार सीमित करने जैसी घटनाएं हाल में चीन की परीक्षा ले रही हैं। चीन इन चुनौतियों का कोई जवाब देता नहीं दिखता और ऐसे में, भारत जैसे दूसरे किरदार उभर रहे हैं। चीन की कई आपत्तियों के बावजूद जी-20 का घोषणापत्र सर्वसम्मति से आया। सबसे पहले, यूक्रेन पर बयान पिछले बाली घोषणापत्र से थोड़ा नर्म है, मगर यह वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाता है। जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आज की परिस्थिति बहुत बदल गयी है- वह इस लड़ाई के विकासशील देशों पर पड़े प्रभाव की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा, पिछले समय में अमेरिका के कई बड़े राजनेताओं के लगातार हुए दौरों के बावजूद, चीन के रवैये में नरमी के संकेत नहीं मिल रहे। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को अड़ियल दिखते चीन के इर्द-गिर्द उभरती भू-राजनीतिक स्थिति को समझना होगा। दूसरा, जी-20 में चीन का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया, जिन्होंने मार्च में ही जिम्मेदारी संभाली है। ली ने सम्मेलन में एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने एक साझा लक्ष्य वाला समुदाय बनाने के लिए चीन के हाल में किये गये प्रयासों का जिक्र किया, और वैश्विक विकास, वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक सभ्यता के प्रयासों का जिक्र किया। लेकिन, जी-20 देशों ने इनमें से किसी पर मुहर नहीं लगायी जो इन विचारों के जरिये चीन के लंबे समय से प्रभाव जमाने की कोशिशों को समझने लगे हैं। पिछले वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के बाद से ही, चीनी नेताओं ने चीन का सामना करने के मकसद से छोटी गुटबाजियां करने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों की आलोचना शुरू कर दी है। इससे पहले, चीन ने अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर में हुई जी-20 की बैठकों का बहिष्कार किया था, तथा बैठक के लोगो से वसुधैव कुटुंबकम को हटाने का भी सुझाव दिया था। जोहानिसबर्ग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के पश्चिमी सेक्टर से फौजों की त्वरित वापसी की मांग को ठुकराने, और चीन के नये नक्शे में अरुणाचल और लद्दाख के बड़े क्षेत्रों को शामिल करने से भी दोनों देशों के बीच की दरार बढ़ी थी। तीसरा, अगले महीने चीन की बीआरआइ परियोजना के बारे में तीसरी शिखर बैठक की योजना के बावजूद बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही। और उधर, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप को जोड़नेवाले आर्थिक गलियारे की योजना में सभी देशों की ओर से बंदरगाह, सड़क, रेल और हाइड्रोजन पाइपलाइन के अलावा डिजिटल संपर्क के लिए सरकारी और निजी भागीदारी की व्यवस्था है। वहीं जी-20 की बैठक से ठीक पहले, जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशिया को भारत के रास्ते पश्चिम एशिया से जोड़नेवाले 'आर्थिक गलियारे' की घोषणा की। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से बीआरआई पर ग्रहण लग सकता है। चौथा, चीन एक समय तीसरी दुनिया की सोच का समर्थन करता था। उसने हाल ही में बीआरआइ में हिस्सा लेनेवाले विकासशील देशों में निवेश किया। लेकिन, लगता है वह आधार भी उसके हाथ से निकल रहा है। चीन के कई विश्लेषकों ने जी-20 के जरिये भारत के विकासशील देशों का अगुआ बनते जाने पर चिंता प्रकट की है। चीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि इससे पहले जी-20 की बैठकों में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ का समर्थन वह करता रहा, लेकिन जी-20 में सदस्यता उसे भारत ने दिलवायी। पांचवां, हाल के समय में जी-20 ने ऐसे कुछ प्रयास शुरु किए हैं, जिनका उद्देश्य कर्ज में बुरी तरह डूबे विकासशील देशों की मदद करना है। चीन इससे भी चिंता में पड़ गया है क्योंकि उसने बहुत सारे देशों को, और अक्सर काफी ऊंचे ब्याज पर, कर्ज दिया हुआ है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के कुल विदेशी कर्ज में चीन का हिस्सा 24 फीसदी है, जबकि निजी बैंकों से उसे 32 प्रतिशत कर्ज मिला है, जिनमें चीन के बैंक शामिल नहीं हैं। विश्व बैंक से उसे 16 प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे संस्थानों से 19 प्रतिशत, और पेरिस क्लब से 10 प्रतिशत कर्ज मिला है। अफ्रीकी संघ के लगभग आधे सदस्य कर्ज में डूबे हैं, ज्यादातर चीन के सरकारी बैंक के कर्ज में।

हिन्द स्वराज

हिन्दुस्तान की दशा-4 (भाग-1)

प्रश्न- आप कहते हैं कि दो आदमी झगड़ें तब उसका न्याय भी नहीं करना चाहिए। यह तो आपने अजीब बात कही।

उत्तर- इसे अजीब कहिये या दूसरा कोई विशेषण लगाइये, पर बात सही है। आपकी शंका हमें वकील-डॉक्टरों की पहचान कराती है। मेरी राय है कि वकीलों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया है, हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े बढ़ाये हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है।

प्रश्न- ऐसे इलजाम लगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित करना मुश्किल होगा। वकीलों के सिवा दूसरा कौन हमें आजादी का मार्ग बताता? उनके सिवा गरीबों का बचाव कौन करता? उनके सिवा कौन हमें न्याय दिलाता? देखिये, स्व. मनमोहन घोष ने कितनों को बचाया? खुद एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। कांग्रेस, जिसके आपने ही बखान किये हैं, वकीलों से निभती है और उनकी मेहनत से ही उसमें काम होते हैं। इस वर्ग की आप निंदा करे यह इन्साफ के साथ गैर-इन्साफ करने जैसा है। यह तो आपके हाथ में अखबार आया इसलिए चाहे जो बोलने की छूट लेने जैसा लगता है।

उत्तर- जैसा आप मानते हैं वैसा मैं भी एक समय मानता था। वकीलों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा मैं आपसे नहीं कहना चाहता। मि. मनमोहन घोष की मैं इज्जत करता हूँ। उन्होंने गरीबों की मदद की थी यह बात सही है। कांग्रेस मे वकीलो ने कुछ काम किया है, यह भी हम मान सकते हैं। वकील भी आखिर मनुष्य है; और मनुष्य-जाति में कुछ तो अच्छाई है ही। वकीलों की भलमनसी के जो बहुतसे किस्से देखने में आते हैं, वे तभी हुए, जब वे अपने को वकील समझना भूल गये। मुझे तो आपको सिर्फ यही दिखाना है कि उनका धंधा उन्हें अनीति सिखाने वाला है। वे बुरे लालच में फँसते हैं, जिसमें से उबरने वाले बिरले ही होते हैं। हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़े हैं। तटस्थ आदमी उनसे कहेगा कि आप गयी-बीती को भूल जायँ; इसमें दोनों का कसूर रहा होगा, अब दोनों मिलकर रहिये। लेकिन वे वकील के पास जाते हैं। वकील का फर्ज हो जाता है कि वह मुवक्किल की ओर जोर लगाये।

क्रमश: ...

विपक्षी अलायंस इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे ये दल

राज कुमार सिंह

इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधनों के बीच होगा। मुंबई में इंडिया का कुनबा बढ़कर 28 हो गया। फिर भी 38 दलों के साथ सत्तारूढ़ एनडीए का कुनबा बड़ा है। बेशक दोनों ही ओर ऐसे दल भी हैं, जिनकी मौजूदगी संसद में नहीं है या नाममात्र की है। मगर इन दलों के पास सीमित क्षेत्रों में ही सही, इतना मत प्रतिशत है, जो कड़े चुनावी संघर्ष में निर्णायक बन सकता है। इसीलिए ऐसे दलों को जोड़ने की कोशिश की गई। फिर भी कुछ अपेक्षाकृत बड़े दल बाहर ही छूट गए या कहें कि उन्होंने तटस्थ रहने का विकल्प चुना। दो एकतरफा लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र की सत्ता के लिए जब 2024 में कड़ा मुकाबला होता नजर आ सकता है, तब इन दलों ने यह मार्ग क्यों चुना? क्या सत्ता से सद्भाव की खातिर या फिर चुनाव के बाद की संभावनाओं के मद्देनजर?

तीन राज्यों के सत्तारूढ़ दलों समेत दर्जन भर दल ऐसे हैं, जो दोनों में से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। इनमें पांच ऐसे दल भी हैं, जो अपने-अपने राज्य में सत्तारूढ़ रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हें लगभग 11 प्रतिशत वोट मिले थे। लोकसभा में इनके 59 सांसद हैं, जो कुल संख्या का लगभग 11 प्रतिशत है।

बात ओडिशा के बीजू जनता दल (बीजेडी) से शुरू करना उचित होगा, जिसके मुखिया नवीन पटनायक का मुख्यमंत्री के रूप में 5वां कार्यकाल चल रहा है। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटें जीतने वाला बीजेडी 2019 में 12 सीटें ही जीत पाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे 45 प्रतिशत वोट मिले। शह-मात के खेल के बावजूद नवीन पटनायक ने कभी केंद्र सरकार या भाजपा से टकराव का रास्ता नहीं चुना। इनके आपसी रिश्तों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री अश्वनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेडी ने एक सीट छोड़ दी।

दूसरा सत्तारूढ़ दल है आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी युवा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मूलतः कांग्रेसी हैं। उनके पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी

अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद जगन मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। अंततः जगन ने कांग्रेस छोड़ अपने पिता के नाम पर वाईएसआरसीपी बनाई और राजनीति के चतुर खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू से सत्ता छीनने में सफल रहे। आंध्र से अब 25 लोकसभा सांसद आते हैं, जिनमें से 22 वाईएसआरसीपी के हैं और शेष तीन नायडू की टीडीपी के। हालांकि टीडीपी 2018 में अलगाव से पहले एनडीए का अंग रह चुकी है, पर इस बीच जगन ने भी मोदी सरकार से अच्छे संबंध बना लिए हैं। वक्त-जरूरत राज्यसभा में मदद भी की है।

टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों का ही आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर नया राज्य बने तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में असर है। दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव महत्वाकांक्षी नेता हैं, जो अपने क्षेत्रीय दल टीआरएस को बीआरएस बना चुके हैं। कांग्रेस-बीजेपी से समान दूरी रखने वाले संघीय मोर्चा के लिए उन्होंने काफी भागदौड़ भी की थी, लेकिन जब पिछले साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया कि कांग्रेस बिना कोई विपक्षी मोर्चा संभव नहीं, तो तटस्थता का रास्ता चुन लिया। चार साल तक एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रामक रहे बीजेपी और केसीआर अब युद्धविराम की मुद्रा में हैं। याद रहे कि इसी साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना से 11 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, जिनमें से फिलहाल नौ केसीआर की पार्टी के हैं।

अतीत में सत्तारूढ़ रह चुके दलों में बीएसपी (यूपी), शिरोमणि अकाली दल (पंजाब), इंडियन नैशनल लोकदल (हरियाणा), टीडीपी (आंध्र प्रदेश) और जेडीएस (कर्नाटक) हैं। बीएसपी का उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में भी कुछ असर रहा है। अकाली दल, टीडीपी और इंडियन नेशनल लोकदल से भाजपा के राजनीतिक रिश्ते रह चुके हैं, तो बीएसपी और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के जेडीएस के रिश्ते सत्ता की खातिर बदलते रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद फिर भाजपा और जेडीएस गठबंधन की चर्चाएं हैं। पिछली बार मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाई जेडीएस पांच लोकसभा सीट मांग रही है, जबकि कुल 28 में से अकेले दम 25 सीटें जीतने वाली भाजपा उसे चार सीटें देने को राजी है। इनके अलावा भी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ समेत सीमित जनाधार वाले कुछ ऐसे दल हैं, जिन्होंने फिलहाल किसी एक पाले में जाने से परहेज किया है। ओवैसी और अजमल के दल खुल कर अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं। इसलिए भी हर गठबंधन उनसे सार्वजनिक तौर पर दूरी ही दर्शाएगा।

फिर भी इन तमाम दलों का अलग से मैदान में उतरना चुनावी गणित को प्रभावित करेगा। इंडिया को ज्यादा नुकसान का अनुमान है, क्योंकि ज्यादातर दल दक्षिण भारत के हैं, जहां भाजपा का बहुत कुछ दांव पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी मायावती की अलग राह इंडिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अगर लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच इतना नजदीकी मुकाबला हुआ कि कोई भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया, तब स्वाभाविक ही सत्ता-संतुलन की चाबी इन तटस्थ खिलाड़ियों के हाथ होगी। वह परिदृश्य दिलचस्प तो होगा ही, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को दूर तक प्रभावित भी करेगा।

कांग्रेस का यह दांव प्रधानमंत्री मोदी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा

अमित शर्मा

भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए %मिशन 80% योजना पर काम कर रही है। उसकी योजना है कि यदि वह अपने सबसे मजबूत गढ़ यूपी को बचाने में सफल हो जाती है तो 2024 में केंद्र की सत्ता में आने की उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो योजना बनाई है, यदि वह सफल हुई तो भाजपा की इस योजना को करारी चोट लग सकती है। इससे केवल भाजपा को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि मायावती को भी अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, चर्चा है कि कांग्रेस यूपी में अपनी वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी को भी प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने अपने दलित नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी मैदान में उतारने का प्लान बना लिया है। उन्हें बाराबंकी या इटावा से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या दलित मतदाता बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती दे सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अब तक मायावती के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे दलित मतदाताओं की एक बड़ी संख्या कांग्रेस के पक्ष में मुड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर और अपने कठोर हिंदुत्व प्लान के जरिए दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने में बड़ी सफलता पाई थी। 2014 से लेकर 2022 तक भाजपा की यही योजना उसे यूपी में बड़ी ताकत बनाने में सबसे कारगर साबित हुई है। ऐसे में यदि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खरगे के रूप में दलित कार्ड खेलती है तो इससे भाजपा को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल, कांग्रेस का यह आइडिया आधारहीन नहीं है। कर्नाटक चुनाव में यह देखा गया है कि दलित मतदाताओं ने जनता दल सेक्युलर जैसी स्थानीय पार्टियों को वोट देने की बजाय निर्णायक भूमिका निभाने वाली कांग्रेस को वोट देना बेहतर समझा। यही कारण है कि एक तरफ जेडीएस के वोट घट गए तो कांग्रेस को वोट शेयरों में बड़ा उछाल आ गया। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग मायावती की प्रभावहीन होती भूमिका से निराश है। वह अपने लिए विकल्प खोज रहा है। इसी विकल्प की तलाश में अति दलित जातियां तो भाजपा के साथ चली गई हैं, लेकिन जाटव के साथ-साथ कुछ जातियां अभी भी अपने लिए विकल्प तलाश रही हैं। कांग्रेस इन्हीं जातियों को अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही है। अभी तक यह चर्चा थी कि कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन के खेमे में लाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन न करने के बसपा के इतिहास और मायावती के बयान को देखते हुए माना जा रहा है कि उनका इंडिया गठबंधन में चुनाव पूर्व न आना तय हो गया है। यही कारण है कि अब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खरगे के सहारे दलित कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार भारद्वाज ने कहा कि बसपा का मतदाता देश के सबसे प्रतिबद्ध मतदाताओं के रूप में देखा जाता रहा है। किसी भी पार्टी के किसी भी झांसे में न आते हुए अब तक वह मायावती को अपना एकमुश्त समर्थन देता रहा है। यही कारण है कि यूपी में शून्य सीटें आने के बाद भी बसपा का वोट प्रतिशत 20 प्रतिशत के लगभग बना रहा। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव इस मामले में आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला साबित हुआ। पहली बार मायावती के वोट बैंक में लगभग 9.35 प्रतिशत की कमी आई, जबकि समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में 10.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। समाजवादी पार्टी को चुनाव में हार के बाद भी 32 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले। इतना वोट उसे मुलायम सिंह के समय में भी कभी नहीं मिले थे। यह विश्लेषण बताता है कि बसपा के मतदाताओं ने मजबूत विकल्प की स्थिति में देखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया था। स्वयं कांग्रेस के भी मतदाताओं ने अखिलेश यादव को मजबूत विकल्प पाते हुए उन्हें वोट दिया जिसके कारण उसका मत प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर हो गया। कांग्रेस अब दलित मतदाताओं को लुभाकर देश के सबसे बड़े राज्य में न केवल अपनी वापसी का रास्ता तैयार करना चाहती है, बल्कि मजबूत विकल्प देकर अपना अस्तित्व भी बचाना चाहती है। उसे भी पता है कि यदि उसने मजबूत विकल्प नहीं दिया तो रहे सहे मतदाता भी विकल्प पाने की कोशिश कर सकते हैं।

बिलासपुर की 24 विधानसभा सीटों पर भाजपा की नजर

ललित कुमार सिंह

बिलासपुर संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव-2018 में बीजेपी को बिलासपुर संभाग में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करने के लिए बीजेपी पूरा फोकस की हुई है। इस मिशन को पूरा करने में बीजेपी के दिग्गज नेता लगे हुए हैं। इसमें बिलासपुर से बीजेपी के सीनियर नेता अमर अग्रवाल, बिलासपुर से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इसी संभाग के जांजगीर चांपा जिले से विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, रायगढ़ जिले से बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी (पूर्व कलेक्टर) आदि के कंधों को पर कमल खिलाने की अहम जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। इस लिहाज से प्रदेश के 11 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट अकेले बिलासपुर संभाग में ही है। इसमें 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में बीजेपी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी फोकस की हुई है। प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर है। 8 जिलों के संभाग में यहां छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा 24 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 13 सीट पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 2 पर बसपा और 2 पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जे (जेसीसीजे) का कब्जा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को बहुत पहले ही जेसीसीजे ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वर्तमान में वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में जेसीसीजे के पास बिलासपुर संभाग में केवल एक ही सीट बची है। बिलासपुर संभाग में उद्योग-धंधे और स्टील पॉवर प्लांट के बड़ी संख्या में होने से यहां पर लाखों की संख्या में यूपी-बिहार के लोग निवासरत हैं। ऐसे में यूपी-बिहार के वोटर्स पर भाजपा की नजर है। वो हर हाल में इन वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की तैयारी में है। उन्हें लुभाने की जुगत में है। रायगढ़ में जिंदल स्टील पॉवर प्लांट, बिलासपुर में स्टील पॉवर प्लांट, सक्ती में स्टील पॉवर प्लांट समेत कई कारखानों में बड़ी सख्या में यूपी-बिहार और झारखंड के लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में इन वोटर्स पर बीजेपी की नजर है। चुनावी साल में रायपुर संभाग के बाद पीएम मोदी का बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिले में आम सभा होने जा रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से हिसाब से बेहद अहम मानी जा रही है। यहां पर पीएम मोदी कई केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही मतदाताओं को प्रभावित भी कर सकते हैं। कुछ बड़ा एलान भी कर सकते हैं। वहीं बिलासपुर संभाग में ही 28 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा प्रस्तावित है। इस दौरान वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर शिरकत करेंगे। पीएम मोदी की रायपुर सभा में करीब 1 लाख से ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। दूसरी और मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में रायगढ़ से ज्यादा भीड़ जुटाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है।

लोकसभा चुनाव में हो सकती है इंडिया गठबंधन की फ्रेंडली फाइट!

आशीष तिवारी

अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक ही चलता रहा तो विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया में सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं, उससे टिकट बंटवारे पर आम सहमति पेचीदा भी होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि कुछ राज्यों में परिस्थितियां फ्रेंडली फाइट की भी बनती जा रही हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों का तो गठबंधन होगा, लेकिन कुछ राज्यों में संभवतया ये पार्टियां एक दूसरे के आमने-सामने भी आ सकती हैं। हालांकि विपक्षी दलों के बड़े नेता अभी ऐसे हालात में बीच का रास्ता तलाश कर जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर आम सहमति बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया में सबसे ज्यादा मशक्कत टिकट बंटवारे को लेकर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में तो टिकट बंटवारे का रास्ता बहुत आसान बना हुआ है, जबकि कई राज्यों में यह बड़ी समस्या भी बनता दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिन राज्यों में बगैर किसी मशक्कत के सीट बंटवारे की राह आसान नजर आ रही है, उसमें तमिलनाडु, झारखंड, पुडुचेरी समेत बिहार और महाराष्ट्र प्रमुखता से शामिल हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और झारखंड राज्यों में लोकसभा की 54 सीटें आती हैं, इसमें 39 सीटें तो सिर्फ तमिलनाडु से ही हैं। यहां पर डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत कई छोटे दल पिछले लोकसभा चुनाव में भी सियासी मैदान में एक साथ थे और विधानसभा के चुनाव में भी एक साथ थे। राजनीतिक विश्लेषक एन. सुदर्शन कहते हैं कि इसलिए इस राज्य में गठबंधन को सीट बंटवारे में बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र और बिहार में भी गठबंधन की ही सरकारें आसानी से चली हैं। इसलिए इन राज्यों में भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है।

सियासी जानकारों का कहना है कि तमिलनाडु की तरह ही पुडुचेरी और झारखंड में भी गठबंधन में शामिल दलों का पहले से ही सामंजस्य बना हुआ है। पुडुचेरी में जहां डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं झारखंड में जेएमएम और राजद समेत कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में चुनाव लड़ते आए हैं।

इसलिए यहां पर भी गठबंधन के सियासी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर बहुत मशक्कत करने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिन राज्यों में गठबंधन में शामिल सियासी दल पहले से ही आपस में मिलकर चुनाव लड़ते आए हैं, उन राज्यों में परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर और आसान नजर आ रही हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जिसमें गठबंधन में शामिल दल आपस में कांटे की टक्कर से सियासी लड़ाई लड़ते आए हैं। उन राज्यों में गठबंधन को सबसे ज्यादा टिकट बंटवारे पर मशक्कत करने की जरूरत लग रही है।

सूत्रों की मानें तो गठबंधन में टिकट बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में नए समीकरणों के लिहाज से बहुत कुछ समायोजन करने और फिर उसी आधार पर टिकट बंटवारे की योजना बन रही है। सूत्रों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से टिकट बंटवारे पर टकराहट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसमें फिलहाल प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, आरएलडी, अपना दल (कृष्णा पटेल) और पश्चिम में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर सीटों को लेकर पेंच इसलिए फंसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 20 से ज्यादा सीटें विपक्षी दलों को नहीं देना चाहती है। जबकि कांग्रेसी आरएलडी और अपना दल समेत चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इसमें 25 सीटें कांग्रेस और 12 सीटें राष्ट्रीय लोक दल की ओर से मांग हो रही है।

इसी तरह टिकटों का सियासी पेंच दिल्ली, पंजाब पश्चिम बंगाल और केरल में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में 42, पंजाब में 14 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अभिजय बनर्जी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट के बीच में सीधी प्रतिस्पर्धा रही है। जबकि यहां के कुछ इलाकों में कांग्रेस का भी अपना मजबूत प्रभाव बना हुआ है। क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, इसलिए वह सीटों के लिहाज से भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रही हैं। पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी है और इन दोनों राज्यों में प्रमुख सियासी दल भी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दो नंबर पर रही थी, इसलिए वह यहां पर सीटों में अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है। पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से आवाज उठ रही है कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर सियासी मैदान में किस्मत नहीं आजमाना चाहती। इसी तरह केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में टिकटों की टकराहट नजर आ रही है।

हालांकि गठबंधन से जुड़े सूत्रों का मानना है कि जल्द ही कुछ समय में सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला निकालकर टिकट की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों का मानना है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर टिकटों के बंटवारे में आपसी सामंजस्य बनता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसमें पंजाब, दिल्ली और केरल समेत उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर इन राज्यों में आपसी सामंजस्य पर सीटों का बंटवारा नहीं होता है, तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। यानी कि जो दल एक राज्य में इंडिया गठबंधन के बैनर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरे राज्य में आमने-सामने भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल एक प्रमुख नेता बताते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल नहीं आने वाली हैं। उनका कहना है कि उनके गठबंधन में शामिल नेता इन सभी सियासी मुद्दों का हल निकाल कर जल्द ही चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं।

विधानसभा चुनावों में भी भाजपा के क्षत्रप हाशिए पर

समीर चौगांवकर

भाजपा के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि जिस प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है उस प्रदेश के दिग्गज नेताओं को भी जानकारी नहीं है कि केन्द्रीय नेतृत्व किसे टिकट देने जा रहा है। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे थे तो इनमें से किसी राज्य के नेता को भनक तक नहीं थी कि टिकट किसे दिया जा रहा है। 17 अगस्त को मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ की 21 सीटों के लिए पहली सूची जारी हो चुकी है। यह भी भाजपा के इतिहास में संभवतः पहली बार ही हुआ है कि संभावित चुनाव की घोषणा से लगभग 3 महीने पहले ही टिकट बांट दिये गये। ऐसी परिस्थिति में तीनों राज्यों की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि इन राज्यों में दशकों से स्थापित नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने अपने को असहाय मान रहे हैं, वहीं केन्द्रीय नेतृत्व उन्हें हाशिए पर करने की पूरी तैयारी कर चुका है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में तीन बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और राजस्थान में पार्टी की एकछत्र नेता रहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेता 2023 के विधानसभा चुनावों की भाजपा की रणनीति के केन्द्र में नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी करने और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनने की जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाल ली है तो वहीं राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। 20 अगस्त को भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का पिछले बीस साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते समय एक प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि %मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव बाद पार्टी करेगी।% शा?ह का बिना लाग लपेट के दिया गया बयान यह बताने के लिए पर्याप्त था कि मध्य प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला मोदी और शाह ही करेंगे।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिये गये शाह के इस बयान का अर्थ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी रूप में लिया गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी चुनाव के बाद मोदी ही करेंगे। शाह के इस बयान ने साफ कर दिया था कि मोदी अब इन तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को आगे करेंगे। इन तीनों राज्यों में भाजपा के पास तकरीबन दो दशक से एक स्थापित नेतृत्व रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ने की रणनीति बना चुकी है। असल में इसके पीछे की रणनीति यह है कि हिन्दी भाषी राज्यों में मोदी का नाम और चेहरा पार्टी से भी बड़ा एक ब्रांड बन चुका है। इसलिए पार्टी स्थानीय नेतृत्व की

परंपरा त्याग कर विधानसभा चुनाव में भी मोदी ब्रांड के सहारे मैदान में उतरना चाहती है। इसलिए न केवल विधानसभा चुनावों के टिकटों का फैसला खुद मोदी कर रहे हैं बल्कि तीनों राज्यों के लिए केन्द्रीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मोदी ही कर रहे हैं ताकि ऐन चुनाव से पहले ये संदेश जाए कि राज्यों में भी सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मांगने हैं।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यह मानता है कि मोदी की अपार लोकप्रियता के बाद भी 2018 के चुनाव में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के लिए भाजपा का स्थानीय नेतृत्व ही जिम्मेदार था। तीनों प्रदेशों के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की लो?कप्रियता को भुनाने में असफल रहे, इसी कारण पार्टी हारी थी। उसके बाद से ही मोदी इन प्रदेशों में नए नेतृत्व को उभारने की दिशा में काम करने लग गए। तीनों प्रदेशों के स्थापित क्षत्रप अपने भरोसेमंद नेताओं को भी यह भरोसा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि वह उनके लिए टिकट की पैरवी करेंगे। मोदी और शाह के विधानसभा चुनावों की कमान संभालने से प्रदेश के नेताओं का दबदबा लगभग खत्म हो गया है और वे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर रहने के लिए विवश हो गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद से ही राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नया और वैकल्पिक नेतृत्व विकसित करने की रणनीति पर मोदी और शाह ने काम शुरू कर दिया था। हालांकि, राजस्थान में मोदी ने इस दिशा में कोशिश राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए ही शुरू कर थी। मोदी ने गजेन्द्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय मंत्री और ओम बिड़ला को लोकसभा स्पीकर बनाकर वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में आगे किया था। उसके बाद ओडिशा से राज्यसभा सांसद लेकिन राजस्थान के मूल निवासी अश्विनी वैष्णव को अति महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर और प्रदेश के अन्य नेताओं को वसुंधरा राजे से अधिक महत्व देकर मोदी ने भविष्य की रणनीति स्पष्ट कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के मानसून सत्र के दौरान राजस्थान के 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर जमीनी हकीकत और राजस्थान पर चर्चा करना यह बताने के लिए पर्याप्त था कि राजस्थान में मोदी ही चेहरा होंगे और पार्टी की रणनीति भी मोदी की देखरेख में बनेगी। राजस्थान में भाजपा हाईकमान ने चुनाव प्रचार अभियान समिति को छोड़कर सभी संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी है और वसुंधरा को कही जगह नहीं दी गयी है। अपने?आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाली वसुंधरा फिलहाल धैर्य का परिचय दे रही हैं और पार्टी हाईकमान के निर्णयों पर प्रतिक्रिया देने से बच रही हैं।

छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो इस छोटे राज्य में भी भाजपा हाईकमान 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को आगे करने की बजाय मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के नेतृत्व में पार्टी को 2018 में सिर्फ 15 सीटों मिली थी। पार्टी ने जनवरी, 2019 में रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और प्रदेश की राजनीति में महत्व कम कर दिया। छत्तीसगढ़ में संगठन और चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम माथुर साफ कह चुके हैं कि?विधानसभा चुनाव में भी चेहरा मोदी ही होंगे। मुख्यमंत्री का फैसला बाद में किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में मोदी को कांग्रेस को हराने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पार्टी में उम्मीद जगाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मोदी ने छत्तीसगढ़ की कमान अमित शाह के हाथ में दे रखी है और वे लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी दौड़ में आगे दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी की कोशिश 2018 की तरह अपमानजनक हार से बचने की है। मोदी और शाह इसमें कितना सफल होते हैं, यह तो परिणाम ही बताएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा रहे शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह मोदी और शाह के सामने बेबस हैं।

नताशा

कविता

जल की रानी मछली

तैर-तैर मछली इठलाती,
जल की रानी है कहलाती।

पंख सुनहरे नित चमकाती,
बिना कांटा पकड़ी नहीं जाती।

पानी में ही जीवित रहती,
पर भूखों का दुख न सहती।

परहित जीवन सदा लुटाती,
बलिदानी जग में कहलाती।

– सुगनचंद्र, नलिन

हंसो हंसाओ

दूध

संता (बंता से)- तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी!
बंता (संता से)- मैं उसे सजा देता हूं।
संता- मैंने सजा दे दी।
बंता- कैसे?
संता- मैं उसकी कटोरी का दूध पी गया।

कोर्ट

वकील- गीता पर हाथ रखकर कहो की..
मुजरिम- ये क्या, सीता पर हाथ लगाया तो कोर्ट में बुलाया, अब फिर गीता पर हाथ!!

शादी

टीचर - बताओ बच्चों कि लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करना चाहिए।
एक लड़का- क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए !
एक लड़की- नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की को अक्ल 18 साल बाद और लड़के को 21 साल बाद आती है !!!

गोली

पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी, क्योंकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि- मैं अपनी जिंदगी, शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूं।

इमरजेंसी

डॉक्टर आधी रात को उठा और पत्नी से बोला- मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं.. फोन आया है इमरजेंसी है।
पत्नी- किसी को तो अपनी मौत मरने दो।

बाल कथा

जीवन जोशी

ईमानदारी की जीत

चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस बीमारी के कारण अपने परिवार का कोई न कोई सदस्य गवाँ चुके थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदर वन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई।

बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह ने किया। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकडू सांप, चिंपू बंदर, गिलू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगलवासियों ने हिस्सा लिया। जब सभी जानवर इकठ्ठे हो गए, तो शेर सिंह एक ऊँचे पत्थर पर बैठ गया और जंगलवासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा, भाइयो, वन में बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गवाँ चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए, ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके।

इस पर जंगलवासियों ने एतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए पैसा कहाँ से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी? इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर इकठ्ठा करेंगे।

यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज! मेरे दो मित्र चंपकवन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊँगा।

इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकठ्ठा करना शुरू कर दिया।

जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में बुला लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे और आधा जंगलवासियों से इकठ्ठा किया जाएगा।

इस प्रकार वन में अस्पताल चलने लगा। धीरे-धीरे वन में फैली बीमारी पर काबू पा लिया गया। दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों की पूरी सेवा करते और मरीज़ भी ठीक हो कर डाक्टरों को दुआएँ देते हुए जाते। कुछ समय तक

सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। परंतु कुछ समय के बाद चीनू खरगोश के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने वीनू खरगोश को अपने पास बुलाया और कहने लगा यदि वे दोनों मिल कर अस्पताल की दवाइयाँ दूसरे वन में बेचें तथा रात में जाकर दूसरे वन के मरीज़ों को देखें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं और इस बात का किसी को पता भी नहीं लगेगा। वीनू खरगोश पूरी तरह से ईमानदार था, इसलिए उसे चीनू का प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने चीनू को भी ऐसा न करने का सुझाव दिया। लेकिन चीनू कब मानने वाला था। उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था। उसने वीनू के सामने तो ईमानदारी से काम करने का नाटक किया। परंतु चोरी-छिपे बेइमानी पर उतर आया। वह जंगलवासियों की मेहनत से खरीदी गई दवाइयों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगा तथा शाम को वहाँ के मरीजों का इलाज करके कमाई करने लगा। धीरे-धीरे उसका लालच बढ़ता गया। अब वह अस्पताल के कम, दूसरे वन के मरीजों को ज्यादा देखता। इसके विपरीत, डॉक्टर वीनू अधिक ईमानदारी से काम करता। मरीज भी चीनू की अपेक्षा डॉक्टर वीनू के पास जाना अधिक पसंद करते। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा शेर सिंह के पास चीनू की शिकायत लेकर पहुँचे। उन्होंने चीनू खरगोश की कारगुजारियों से राजा को अवगत कराया और उसे दंड देने की माँग की। शेर सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि सच्चाई अपनी आँखों से देखे बिना वे कोई निर्णय नहीं लेंगे। इसलिए वे पहले चीनू डॉक्टर की जांच कराएँगे, फिर अपना निर्णय देंगे। जांच का काम चालाक लोमड़ी को सौंपा गया, क्योंकि चीनू खरगोश लोमड़ी को नहीं जानता था। लोमड़ी अगले ही दिन से चीनू के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन उस पर नज़र रखने के बाद लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उसने इस योजना की सूचना शेर सिंह को भी दी, ताकि वे समय पर पहुँच कर सच्चाई अपनी आँखों से देख सकें। लोमड़ी डॉक्टर चीनू के कमरे में गई और कहा कि वह पास के जंगल से आई है। वहाँ के राजा काफी बीमार हैं, यदि वे तुम्हारी दवाई से ठीक हो गए, तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। यह सुनकर चीनू को लालच आ गया। उसने अपना सारा सामान समेटा और लोमड़ी के साथ दूसरे वन के राजा को देखने के लिए चल पड़ा। शेर सिंह जो पास ही छिपकर सारी बातें सुन रहा था, दौड़कर दूसरे जंगल में घुस गया और निर्धारित स्थान पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी डॉक्टर चीनू को लेकर वहाँ पहुँची, जहाँ शेर सिंह मुँह ढँककर सो रहा था। जैसे ही चीनू ने राजा के मुँह से हाथ हटाया, वह शेर सिंह को वहाँ पाकर सकपका गया और डर से काँपने लगा।

अनोखी तरकीब

बहुत पुरानी बात है। एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गयी। बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुँचा और चोरी के बारे में बताया।

सबकुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को बुलाया। जब सब सामने पहुँच गए तो काजी ने सब को एक-एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बराबर थीं। न कोई छोटी न बड़ी। सब को छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने अपने घर ले जाएँ और कल सुबह वापस ले आएँ। इन सभी छड़ियों की खासियत यह है कि यह चोर के पास जा कर ये एक उँगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती हैं। जो चोर नहीं होता, उस की छड़ी ऐसी की ऐसी रहती है। न बढ़ती है, न घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ।

काजी की बात सुन कर सभी अपनी अपनी छड़ी ले कर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उस ने सोचा, अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उँगली बड़ी निकली तो वह मुझे तुरंत पकड़ लेंगे। फिर न जाने वह सब के सामने कैसी सजा दें। इसलिए क्यों न इस विचित्र छड़ी को एक उँगली काट दिया जाए। ताकि काजी को कुछ भी पता नहीं चले। चोर यह सोच बहुत खुश हुआ और फिर उस ने तुरंत छड़ी को एक उँगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिसघिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही न चले कि वह काटी गई है।

अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और खुशीखुशी चादर तान कर सो गया। सुबह चोर अपनी छड़ी ले कर खुशी खुशी काजी के यहाँ पहुँचा। वहाँ पहले से काफी लोग जमा थे।

काजी 1-1 कर छड़ी देखने लगे। जब चोर की छड़ी देखी तो वह 1 उँगली छोटी पाई गई। उस ने तुरंत चोर को पकड़ लिया। और फिर उस से व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया। चोर को जेल में डाल दिया गया।

सभी काजी की इस अनोखी तरकीब की प्रशंसा कर रहे थे।

सेहत

नकसीर के घरेलु उपचार

चिलचिलाती धूप में अक्सर कुछ लोगों को नाक से खून बहने की शिकायत होती है। इसे नकसीर भी कहा जाता है। यह मौसम के अनुसार शरीर में अधिक गर्मी बढ़ने से भी हो सकता है और कुछ लोगों को अधिक गर्म पदार्थ का सेवन करने से भी। पेश है नकसीर से निपटने के घरेलू उपचार-

- प्याज को काटकर नाक के पास रखें और सूंघें।
- काली मिट्टी पर पानी छिड़ककर इसकी खुशबू सूंघें।
- रुई के फाए को सफेद सिरका में भिगोकर उस नथुने में रखें, जिससे खून बह रहा हो।
- जब नाक से खून बह रहा हो तो कुर्सी पर बिना टेका लिए बैठ जाएं, नाक की बजाय मुंह से सांस लें।
- सिर को आगे की ओर झुकाएं न कि पीछे की ओर।
- ठंडे पानी में भीगे हुए रुई के फाए को नाक पर रखें। रुई के छोटे-छोटे फायों को पानी में भिगोकर फ्रीजर में रख लें। इनसे सिकाई करें।
- किसी भी प्रकार के धूम्रपान (एक्टिव या पैसिव

दोनों) से बचें।
- साफ हरे धनिए की पत्तियों के रस की कुछ बूंदें नाक में डाल लें।
- इन उपायों के अलावा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से भी राहत मिलेगी।

जानकारी

कभी सोडा के बिना बेचा जाता था कोका कोला

कोका कोला का स्लोगन- ठंडा मतलब कोका कोला.. आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। कोका कोला की प्रसिद्धि पर गौर किया जाए तो दुनिया भर में आज प्रति सैकेंड लगभग आठ हजार गिलास कोका कोला पिया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह ठंडा पेय कहां से आया और इसके आविष्कारक कौन थे।

गर्मियों में ठंडक देने वाले इस शीतल पेय का आविष्कार अटलांटा, अमेरिका के एक दवा विक्रेता डॉ. जॉन स्टिच पेमबर्टन ने किया था। उन्होंने 1886 में कोका के पत्ते और %अफ्रीकी कोला% नामक बादाम के प्रयोग से इस पेय को तैयार किया था। यह न सिर्फ एक शीतल पेय था, बल्कि दिमाग को तरोताजा करने वाला भी था। जब इसे बाजार में लाया गया तो इसे पसंद करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। डॉ. पेमबर्टन के एक पार्टनर फ्रेंक एम. राबिन्सन जो कि किताबों के विक्रेता थे, ने उनके इस पेय को %कोका कोला% नाम दिया।

दोस्तों, अपने आविष्कार के समय कोका कोला बिना सोडा के साथ बेचा गया। एक दिन पेमबर्टन की दवा की दुकान पर सिरदर्द और गर्मी से बेहाल एक ग्राहक आया उसने पेमबर्टन से आग्रह किया कि वह कोका कोला को सोडा के साथ पीना चाहता है। पेमबर्टन ने कोका कोला को सोडा के साथ मिलाकर ग्राहक को दिया और खुद भी पिया। स्वाद में यह बिना सोडा मिश्रित कोका कोला से भी बेहतर और तुरंत राहत पहुंचाने वाला था, और तब से सोडा मिला कोका कोला ही बेचा जाने लगा।

1888 में पेमबर्टन की मौत के बाद 1891 में कोका कोला को बेचे जाने का अधिकार अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के चांसलर ग्रिग्स कैंडलर ने खरीदा और 1892 में इसे एक कंपनी का रूप दिया। 1894 में कोका कोला को बोतल में पैक कर पूरे अमेरिका में बेचा जाने लगा।

1915 में कोका कोला की बोतल को नया लुक दिया गया क्योंकि उस समय तक अमेरिका में जो भी शीतल पेय मिलते थे उनकी बोतल का डिजाइन एक जैसा था। बाजार में अलग दिखाने के लिए कोका कोला की बोतल को अलग तरह से डिजाइन कराकर उसका पेटेंट कराया गया। इस बोतल का डिजाइन रूट ग्लास कंपनी के डिजाइनर अर्ल आर डीन ने तैयार किया।

जीव जंतु

मैडागास्कर में पाया गया डेढ़ इंच का गिरगिट

गिरगिट छिपकली की एक प्रजाति है, जिसे उसकी रंग बदलने की विशिष्टता के लिए जाना जाता है। प्रमुख रूप से यह अफ्रीका, मैडागास्कर, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण एशिया में पाया जाता है। अभी तक इसकी 160 से भी ज्यादा प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं।

हाल ही में अमेरिका तथा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मैडागास्कर द्वीप के उत्तरी हिस्से में गिरगिट की चार और ऐसी प्रजातियों की खोज की है जो आकार में बहुत ही छोटी हैं। वैज्ञानिकों के लिए इतने छोटे आकार के जीव को ढूंढ पाना मुश्किल था किन्तु इन जीवों की प्रकृति के आधार पर न सिर्फ इन्हें ढूंढा जा सका बल्कि इनके बारे में बहुत कुछ जाना भी जा सका। खोजकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि एक बार इसके पाए जाने वाले स्थान का पता चल जाए तो इसे आसानी से पकड़ा भी जा सकता है क्योंकि ये गिरगिट दिन के समय भले ही पेड़ की पत्तों की परतों में छिपे रहते हों किंतु रात होने पर यह सोने के लिए टहनियों पर आ जाते हैं और रात भर एक ही जगह पर रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मैडागास्कर में पाई गई गिरगिट की ये चारों प्रजातियां इतनी छोटी हैं कि सिर्फ देखने भर से इनमें भिन्नता का पता लगा पाना कठिन है। इनमें एक प्रजाति जिसे %ब्रूकेशिया माइक्रा% के नाम से जाना जा रहा है, दुनिया में अब तक प्राप्त गिरगिट की प्रजातियों में सबसे छोटी है। इसमें मिले सबसे छोटे गिरगिट की लंबाई महज 1.3 इंच थी। वैसे आम तौर पर इस प्रजाति के एक पूर्ण विकसित गिरगिट की लंबाई मात्र 2.9 इंच ही है, जबकि इस प्रजाति के नर गिरगिट की लंबाई महज 1.6 इंच तक ही पाई गई। खोजकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रुकेशिया माइक्रा इतना छोटा है कि इसे एक माचिस की तीली के सिरे पर बैठाया जा सकता है। दुनिया का यह सबसे छोटा गिरगिट मैडागास्कर में एक निर्जन टापू पर पड़े कंकड़-पत्थरों पर मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति इन टापुओं पर पाए जाने के कारण यहां के वातावरण में अपने को ढालने में छोटी होती चली गई। मैडागास्कर में प्राप्त इस तरह के गिरगिटों का रहवास मात्र एक वर्ग किलोमीटर जगह तक ही सीमित है।

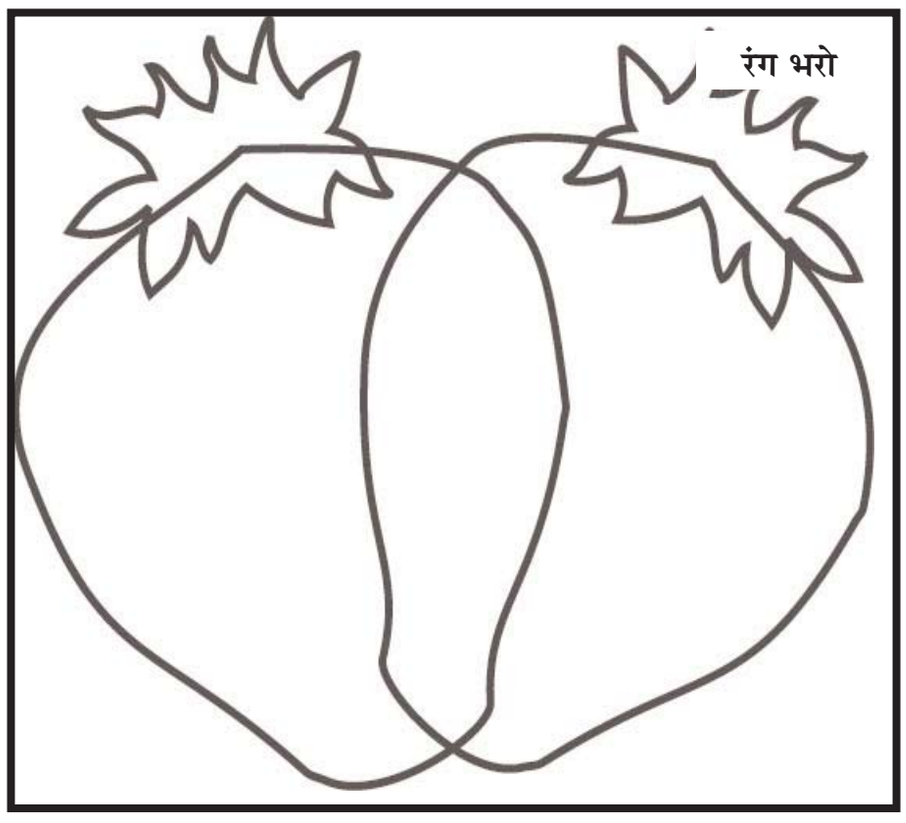

क्या आप जानते हैं

गाने बजाने वाले ज्यादा बुद्धिमान

स्कूलों में अब वार्षिकोत्सव की धूम रहती है। ऐसे मौकों पर स्टूडेंट्स गायन और वादन की प्रस्तुति से सभी को इम्प्रेस करते हैं। गायन या वादन में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स को अपने इस शौक के कारण साल के बाकी समय घर वालों की डाँट भी सुनने को मिलती होगी या कई जगह इस रुचि को बढ़ावा भी दिया जाता होगा। खैर इन दिनों विज्ञान की दुनिया से जो खबर आई है वह वाद्ययंत्र बजाने वालों के पक्ष में है।

विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैं कि वाद्ययंत्र पर नियमित अभ्यास करने वाले अपने दूसरे साथियों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसे संगीतज्ञों का आईक्यू भी दूसरों के मुकाबले 7 प्वाइंट्स तक ज्यादा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नियमित अभ्यास करने वालों में दिमाग का वह हिस्सा ज्यादा विकसित होता है जिससे संगीत सुना और समझा जाता है। इस हिस्से के विकसित होने के कारण न सिर्फ संगीत बल्कि दूसरी चीजों को समझना भी इन संगीत रसिकों के लिए आसान होता है।

वैज्ञानिक अपनी बात के समर्थन में कहते हैं कि संगीत सीखने से और भी कई फायदे हैं जैसे संगीत में नोट्स और बीट्स पकड़ने वाले स्टूडेंट अलर्ट रहना सीख जाते हैं। एक सुर के बाद अगला सुर क्या होगा इससे उन्हें प्लानिंग करना आ जाता है और संगीत के साथ उनकी भावनात्मक समझ भी बेहतर हो जाती है।

युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के मनोवैज्ञानिक लुत्ज जैक का कहना है कि वाद्य यंत्र सीखने से बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। वे कहते हैं कि जब बच्चे संगीत के साथ भावों को समझना सीख जाते हैं तो उनके लिए एक से ज्यादा फोरेन लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि तब वे भाषा की टोन से समझ जाते हैं कि बात का मतलब क्या है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में अभियंताओं की सराहना की

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अभियंता दिवस (इंजीनियर्स डे) पर अभियंताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका नवोन्वेषी मस्तिष्क और अथक समर्पण देश की प्रगति की रीढ़ है। अभियंता दिवस तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के दीवान एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है, जिन्हें इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए जाना जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था, उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, इंजीनियर दिवस पर सभी मेहनती इंजीनियरों को बधाई! उनका नवोन्मेषी मस्तिष्क और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ रहा है। अवसंरचनात्मक चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक, उनका योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है।

गहलोत सरकार पर अनुराग ठाकुर का वार

नईदिल्ली। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। यही कारण हैं कि दोनों दलों के बीच वार-पलटवार देखने को मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनाव में महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साढ़े चार साल आप जनता को लूटते रहे। (राजस्थान में) पेट्रोल-डीजल के दाम सबसे अधिक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक महंगाई है जिसका मूल कारण गहलोत जी की सरकार है। आज राजस्थान में पेट्रोल पंप क्यों बंद हैं? क्यों राजस्थान के लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यह लूट की खुली छूट, यह गहलूट सरकार में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान और अन्य कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों में सरकारों ने अपना वैट बढ़ाया, भाजपा शासित राज्यों ने कम किया है।

सिसोदिया की जमानत पर 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सिसोदिया कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की पीठ ने सिसौदिया के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू के संयुक्त अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। सिंघवी ने अदालत से कहा कि मामले की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि सिसोदिया अपनी पत्नी की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित विसंगतियों के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में लंबित अलग-अलग मामलों में नियमित जमानत की भी मांग की है।

केसीआर की बेटी कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को एक समन जारी किया था। इस समन पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। दरअसल, जांच एजेंसी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 15 सितंबर को जांच में शामिल होने को लेकर समन जारी किया था। इसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद, शीर्ष अदालत ने ईडी के समन पर 26 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी। वहीं, ईडी ने अदालत में कहा कि तेलंगाना सीएम की बेटी को 26 सितंबर तक पेश होने के लिए नहीं कहेंगे। हालांकि, इससे पहले ईडी मुख्यालय में कविता से मार्च में कई बार पूछताछ की जा चुकी है। दरअसल, एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल आठ जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे।

भाजपा ने उत्तरप्रदेश में बदले 69 जिलाध्यक्ष

लखनऊ। यूपी भाजपा ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। पूरे यूपी से 75 प्रतिशत से अधिक जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रहीं थीं। शुक्रवार को यह फेरबदल कर दिया गया। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। करीब दो महीने से इस बारे में चर्चाएं चल रही थीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए यह नियुक्तियां की गई हैं। 98 जिलों में 69 जिलाध्यक्ष नए बनाए गए हैं और 29 पुराने जिलाध्याक्षों पर ही दांव लगाया गया है।हालांकि इस सूची में महिलाओं को जगह कम मिली है। मात्र पांच महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ महानगर में आनंद द्विवेदी, लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं।

इंडिया गठबंधन पर संबित पात्रा का तंज

जिसका सच में बहिष्कार किया जाना चाहिए उसका नाम राहुल गांधी है

नईदिल्ली। सनातन धर्म को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भजपा जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों पर हमलवार है। आज एक बार फिर से भाजपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबीत पात्रा ने कहा कि आज हम सुबह से भारतीय सेना के उन अफसरों और जवानों की अंतिम यात्रा को देख रहे थे, जिन्होंने मां भारती के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी भी वहां आतंकी हमलों पर कार्रवाई जारी है। इन सबके बीच कुछ नेता ऐसे हैं, जो देश विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से न केवल बात करनी चाहिए अपितु आतंकवादियों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे भी समझने को कोशिश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को करनी चाहिए।

पात्रा ने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस की सोच है, सैफुद्दीन सोज वही कांग्रेसी नेता है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जम्मू कश्मीर अलग होना चाहिए। वही आज इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को कांग्रेस सड़क का गुंडा कहती है और आतंकवादी के मन को पढ़ने की बात करती है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 10 मई 1951 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। विशेष रूप से, यह संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था; इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के साधन प्रदान किए।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक फर्जी थे, आप हमें सबूत दिखाइए। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूछते हैं कि बताओ भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए थे बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं कि तो जायज है, इनका कोई बॉयकाट नहीं होता। लेकिन जब पत्रकार

किसी डिबेट में इनसे सवाल पूछ लेता है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो ये पत्रकारों का बॉयकाट कर देते हैं। क्यों नेता भगवान हैं क्या? ये भगवान पर सावल उठा सकते हैं लेकिन पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिसका सच में बहिष्कार करना चाहिए उसका नाम राहुल गांधी है। नेता में दम नहीं है। आप किस-किस का बहिष्कार करेंगे। उन्हें छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है।

संबित पात्रा ने कहा कि मुझे उस अवार्ड वापसी गैंग से जो मोमबत्ती वाले हैं, उनसे एक सवाल पूछना है कि आज शाम कहीं सुलगाएंगे या नहीं। यही लिस्ट अगर हमारी तरफ से जारी हुई होती तो बाजार में मोमबत्ती कम पड़ जाती, मोमबत्ती ब्लैक में बिक रही होती। सारे मोमबत्ती कल से खरीद कर घूम रहे होते। एक भी मोमबत्ती खरीदी गई है या नहीं? ये अवार्ड वापसी गैंग एक भी अवार्ड वापस करेगी? उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्रीराम चरित्र मानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया। लिस्ट जारी करने वालों के मुह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या आप इस मंत्री का बहिष्कार करेंगे या नहीं। राहुल गांधी जवाब दीजिए। आपमें हिम्मत है उस राजनीतिक पार्टी और उस नेता का बहिष्कार कर सकते हैं क्या?

कांग्रेस नेता और फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर बीजेपी हमलावर, कहा- भारत जवाब देगा

जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए का अभियान जारी है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऊंचे इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में भारतीय सेना को दो अफसर, जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक डीएंसी और एक सेना के एक जवान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। लेकिन इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने भी विवादित बयान दिया।

इन नेताओं के बयानों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फारुक अब्दुल्ला और सैफुद्दीन सोज के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का मत साफ है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं हो सकती। पात्रा ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी करना दुखद है। संबित पात्रा ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि जब देश में ऐसी स्थिति (अनंतनाग मुठभेड़) सामने आ रही है, तब भी कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं जो देश के खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि भारत को न केवल पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए बल्कि पीएम मोदी को ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आतंकियों के मन में क्या चल रहा है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। जहां तक ??फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं की बात है तो उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की बात कही है। भारत ने कहा है और हजार बार कहा गया है कि बातचीत और आतंक कभी एक साथ नहीं चल सकते। फिर भी, जब सैनिक अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं - यह न केवल अनुचित है, बल्कि दुखद भी है। भारत जवाब देगा।

जनता इंडिया गठबंधन को करेगी ब्लैकलिस्ट : सिंधिया

टीवी एंकरों की सूची देखकर भड़के ज्योतिरादित्य

नईदिल्ली। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों ने गुरुवार को फैसला किया कि वे देश के 14 टीवी एंकर के प्रोग्राम में प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। यह फैसला 'इंडिया' की मीडिया से संबंधित समिति की बैठक में लिया गया। इसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों का दिल काला होता है, वे ही ब्लैकलिस्टिंग के ऐसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में उत्तर से दक्षिण तक इंडिया गठबंधन की भूमिका आप देखिएगा क्या होगा। इस गठबंधन को जनता ब्लैक लिस्ट में डालने वाली है।

कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने एंकरों की सूची जारी की थी और बताया था कि रोज शाम पांच बजे से कुछ चैनलों पर नफरत की दुकानें सजायी जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। जारी सूची में अर्णब गोस्वामी, अमीष देवगन, चित्रा त्रिपाठी, रुबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, आनंद नरसिम्हन, अशोक श्रीवास्तव, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, शिव अरुर और सुशांत सिन्हा शामिल हैं।

इधर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 'इंडिया' के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उसके घटक दो ही काम कर रहे हैं, एक सनातन संस्कृति को कोसना और दूसरा मीडिया को धमकी देना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्षी गठबंधन के इस कदम की तुलना आपातकाल से की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह कदम उनकी हताशा को दर्शाता है। हर दिन कांग्रेस और उनके सहयोगियों के नेता कहते हैं कि वे सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे और हिंदुओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब उन्होंने पत्रकारों का भी बहिष्कार शुरू कर दिया है और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। 'नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' ने बहिष्कार को लोकतंत्र

पर हमला करार दिया।

इधर, इंडिया गठबंधन द्वारा कई टीवी समाचार एंकरों का बहिष्कार करने पर लोक जनशक्ति पार्टी(राम विलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम दल एक साथ आते हैं और कुछ पत्रकारों की एक सूची जारी करते हैं कि हम इन पत्रकारों का बहिष्कार करेंगे, ये आपातकालीन स्थिति है या नहीं? जो आपके मन मुताबिक नहीं है, आप उनका बहिष्कार करेंगे। उन्हें इन प्लेटफॉर्म का इस्तमाल करना चाहिए। इस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहिष्कार करना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हर समय आपके अनुसार सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कई पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष से भी सवाल किए जाएंगे की आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। हम इसकी निंदा करते हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन वाले लोग यह प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं मानते। अगर आपके पास सही उत्तर है तो आप आएं। आप प्रश्नों से क्यों डरते हैं? ऐसे भी चैनल हैं जहां बीजेपी के खिलाफ बोला जाता है लेकिन बीजेपी ने कभी उनका बहिष्कार नहीं किया क्योंकि हमारे पास उत्तर हैं। आपातकाल से अब तक वे प्रेस के खिलाफ हैं। मैं इसका खंडन करता हूं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को फाइनल मुकाबला

कोलंबो। श्रीलंका ने एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में पाकिस्तान को दो विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब श्रीलंका 17 सितंबर रविवार को भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगा। पाकिस्तान के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मेंडिस की 87 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से 91 रन की पारी और समरविक्रम (48) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 100 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर आठ विकेट पर 252 रन बनाकर जीत दर्ज की।

श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षाना मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल में खेलना संदिग्ध है। तीक्षणा की चोट की गंभीरता का पता स्कैन के बाद चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को श्रीलंका की दो विकेट की जीत के दौरान क्षेत्ररक्षण करते समय तीक्षणा के दायें हैमस्ट्रिंग (पैर की मांसपेशियों) में खिंचाव आ गया। श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''महेश तीक्षाना की दाहिनी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। खिलाड़ी की स्थिति का पूरी तरह से आकलन करने के लिए उसका स्कैन किया जाएगा।'' इस मैच में श्रीलंका की गेंदबाजी के दौरान तीक्षणा को कई बार लंगड़ा कर चलते और मैदान के बाहर जाते देखा गया। उन्होंने चोट के बावजूद 42 ओवर के मैच में अपने नौ ओवर के स्पैल को पूरा किया। वह पाकिस्तान की पारी के दौरान 39वें ओवर में टीम के अन्य सदस्यों की मदद से मैदान के बाहर गये। तीक्षाना की चोट ने श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि पहले से ही वानिंदु हसरंगा, दुश्मंथा चमीरा, लाहिरू मदुशंका और लाहिरू कुमारा जैसे अहम खिलाड़ी चोट के कारण टीम से बाहर हैं। श्रीलंकाई टीम रविवार को फाइनल में भारत से भिड़ेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 16 साल बाद लगातार 11वें दिन चढ़ा

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भी तेजी बरकरार रखी और इसी के साथ यह अपने इतिहास के नए मुकाम पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार 11वें कारोबार सेशन में तेजी बरक़रार रखी है। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स लगातार चढ़ते हुए अपने ऑल टाइम हाई लेवल 67,838 अंक पर पहुंच गया। साथ ही निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड लेवल 20,180 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी निवेशकों की ताजा खरीदारी से बाजार में तेजी आई। इसके अलावा दूरसंचार, ऑटो और तकनीकी शेयरों में खरीदारी से भी बाजार को बढ़त के साथ स्थिर होने में मदद मिली। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 319.63 अंक 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 67,838.63 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 67,927.23 अंक तक चला गया था। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 67,519.00 अंक पर बंद हुआ था।

इंफोसिस ने ग्लोबल कंपनी के साथ किया अरबों का सौदा

नईदिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने एक ग्लोबल कंपनी के साथ 1.5 अरब डॉलर का सौदा किया है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह सौदा 15 साल के लिए होगा। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि इस सौदे के तहत इंफोसिस कंपनी के प्लेटफार्मों और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस का लाभ उठाते हुए बेहतर डिजिटल एक्सपीरिएंस और बिजनेस ऑपरेटिंग सर्विस प्रदान करेगी। हालांकि, इंफोसिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह कौन सी कंपनी है जिसके साथ यह सौदा कर रही है। महीने की शुरुआत में, अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया ने जेनरेटर एप्लिकेशन डेवलप करने के लिए भारतीय समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एआई पार्टनरशिप की घोषणा की।

शाओमी की सप्लायर कंपनी खोलेगी भारत में प्लांट

नईदिल्ली। स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की सप्लायर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बड़ी नई फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार है। भारत चीनी टेक कंपनियों पर लोकल असेंबलिंग फर्म के साथ मिलकर काम करने करने के लिए दबाव डाल रहा है ऐसे में शाओमी की सप्लायर कंपनी नई फैक्ट्री खोलेगी। मामले से परिचित लोगों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि डिक्सन फैक्टरी में तीन वर्षों में 4 अरब रुपये (48.2 मिलियन डॉलर) से ज्यादा का निवेश करेगी। फैक्टरी 300,000 वर्ग फुट से ज्यादा या छह फुटबॉल मैदानों के आकार में फैली हुई है और यह बड़े पैमाने पर शाओमी स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करेगी। सूत्रों ने कहा कि इस महीने के अंत में एक सरकारी अधिकारी द्वारा प्लांट का उद्घाटन किया जाना तय है।चीन की कंपनी शाओमी को स्मार्टफोन असेंबलिंग के लिए डिक्सन के साथ साझेदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

ऑनलाइन सेल 90000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद

नईदिल्ली। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में सालाना आधार पर 18-20 प्रतिशत की ग्रोथ होने के साथ ही इसके 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के अनुसार, आगामी त्योहारी सीजन संभावित रूप से मार्जिन के मामले में अब तक का सबसे सफल सीजन हो सकता है। रेडसीर ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि भारत ईटेलिंग के 2023 त्योहारी महीने का जीएमवी (सकल व्यापारिक मूल्य) करीब 90,000 करोड़ रुपये रहेगा जो पिछले साल के त्योहारी महीने की बिक्री से 18-20 प्रतिशत अधिक है।' कंपनी के अनुसार, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करीब 14 करोड़ लोगों के इस त्योहारी महीने के दौरान कम से कम एक बार ऑनलाइन खरीदारी करने की उम्मीद है।

दशकों तक भारत तेल-एलपीजी का खरीदार था अब बनेगा ऊर्जा साझेदार

अभिनय आकाश

नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया। सऊदी अरब और भारत दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि 100 अरब डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सऊदी अरब भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करना चाहता है और इसमें विशाल रिफाइनरी भी शामिल है। यही नहीं भारत और सऊदी अरब ऊर्जा से लेकर रक्षा तक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने जा रहा है। भारत और सऊदी अरब संयुक्त रूप से हथियार बनाने पर भी सहमत है। भारत और सऊदी अरब ने अपने बिजली ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताते हुए अपने पारंपरिक तेल क्रेता-विक्रेता संबंध को ऊर्जा साझेदारी में बदलने की योजना बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और उनके सऊदी समकक्ष अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल-सऊद द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, भारत की स्थिति को सऊदी तेल और रसोई गैस (एलपीजी) के शुद्ध खरीदार से हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा निर्यातक में बदलने की क्षमता रखता है।

सऊदी अरब भारत के लिए तेल का तीसरा सबसे बड़ा और एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार ने एक बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। इंटरकनेक्ट दूरगामी परिणाम वाला सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि यह दोनों

अर्थव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांध देगा। दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 केबल परिचालन में हैं, जिनमें सबसे लंबा ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर लंबा वाइकिंग लिंक है। जब भी यह साकार होगा, यह मुख्य रूप से हरित ऊर्जा के लिए वैश्विक ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड दृष्टिकोण में पहला ऑफशोर लिंक होगा। दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 बिजली केबल परिचालन में हैं, जिनमें सबसे लंबा यूके और डेनमार्क के बीच वाइकिंग लिंक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक सकारात्मक पहलू यह है कि बयान में सहयोग के उद्देश्यों में ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करके चिन्हित क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना सूचीबद्ध किया गया है।

विनीत मित्तल के नेतृत्व वाली अवाडा एनर्जी और रुइयास प्रवर्तित एस्सार समूह द्वारा सऊदी अरब में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए क्रमश: एईडब्ल्यू (अल जोमैह एनर्जी एंड वॉटर) और डेजर्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की घोषणा के साथ क्रॉस-निवेश के शुरुआती संकेत सामने आए, जहां एस्सार 4.5 बिलियन डॉलर का हरित इस्पात संयंत्र का निर्माण कर रहा है। समझौता ज्ञापन पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में सहयोग पर भी केंद्रित है। एक ऐसा कदम जो भारत की रणनीतिक तेल और गैस भंडारण क्षमताओं के विस्तार में सऊदी निवेश को जन्म दे सकता है। भारत के पास वर्तमान में 5 मिलियन टन से कुछ अधिक का रणनीतिक तेल भंडार है जो तीन स्थानों पर फैला हुआ है और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एलपीजी को एक गुफा में संग्रहीत करता है।

भारत ने 2008 में मन्नार की खाड़ी के पार श्रीलंका के साथ 500 मेगावाट के समुद्री बिजली लिंक का प्रस्ताव रखा था। सरकारी कंपनी पावरग्रिड ने तब इसकी लागत 2,292 करोड़ रुपये आंकी थी और कहा था कि इसे 42 महीनों में पूरा किया जा सकता है। लेकिन श्रीलंका के रुख बदलने के बाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। भारत वर्तमान में बांग्लादेश और नेपाल को बिजली निर्यात करता है और भूटान से बिजली आयात करता है। नई दिल्ली म्यांमार और उससे आगे तक ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर विचार कर रही है।

हटा दीं तुमने दीवारों से सब तस्वीरें पुरखों की...

भाजपा, आरएसएस के लोग महात्मा गांधी की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते.... लेकिन वहां गांधी को इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का जोर है। गांधी देश के साथ-साथ ब्रांड गुजरात भी हैं। सरदार पटेल भी ब्रांड गुजरात हैं,इसलिए गांधी,पटेल और मोदी के बहाने यह दिखाने की कोशिश है कि आजादी से पहले,उसके बाद और अब 21वीं सदी का भारत बनाने में ब्रांड गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है... इधर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के पी?म ऋषि सुनक,संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस सहित जी 20 देशों के प्रमुख नेताओं ने महात्मा गाँधी के समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर भारत के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की,वहीं पीएम मोदी ने राजघाट पर सभी की अगवानी की। सवाल यही खड़ा होता है कि भाजपा के कुछ नेता गाँधी के खिलाफ टिप्पणी तथा उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने में पीछे नहीं हैं पर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है।क्या गाँधी के खिलाफ टिप्पणी को राजद्रोह नहीं माना जाना चाहिये।वैसे बड़े ब्रांड वैल्यू की वजह से स्वच्छ भारत अभियान और ग्राम स्वराज के बहाने भाजपा ने कांग्रेस से महात्मा गांधी को राजनीतिक तौर पर टेकओवर करने की कोशिश शुरू कर दी थी ?दरअसल भाजपा को गाँधी को नजरअंदाज करना संभव भी नहीं है क्योंकि इनका कोई आइकन भी तो नहीं है न आजादी के समय का और न उसके बाद के कालखंड का... अब देखते हैं कि बापू के खिलाफ क्या टिप्पणी भाजपा नेताओं ने की है....भाजपा के तत्कालीन प्रमुख अमित शाह ने जून 2017 में गांधी कोचतुर बनिया (चालाक बनिया) बताया,जो उनकी चतुराई का संदर्भ था । व्यापारिक जाति जिसमें उनका जन्म हुआ।

स्वतंत्रता हासिल करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं और सोच के लोगों ने खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ा। कांग्रेस के पास कोई विचारधारा या सिद्धांतों का सेट नहीं था और इसका उपयोग केवल स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में किया गया थाऔर इसलिए,महात्मा गांधी, दूरदर्शिता के कारण,बहुत चतुर बनिया था,उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है।भोपाल से भाजपा की लोकसभा सांसद और मालेगांव विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बार-बार महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है।

पिछले साल लोकसभा चुनाव के बीच सिंह ने कहा था कि गोडसे देशभक्त था और वह देशभक्त ही रहेगा।हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया कि महात्मा गांधी की छवि से खादी को मदद नहीं मिली और इससे मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया,विज ने लोकप्रिय हिंदी गीत साबरमती के संत पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गलत तस्वीर पेश की गई है और दावा किया कि इसके गीत कई शहीदों का अपमान थे जिनके योगदान को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।असम से भाजपा के राज्यसभा सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा ने महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की तुलना कचरा से की थी।

जी-20 में करीब 4100 करोड़ ख़र्च.?

भारत में जी-20 सम्मेलन का भव्य आयोजन अगले आयोजक देश ब्राजील के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।जी-20 सम्मेलन पर खर्च को लेकर सरकार ने अभी कोई अधिकारिक आंकड़ा नहीं पेश किया है, लेकिन अनुमानित तौर पर पर 4100 करोड़ रुपये के खर्च की बात सामने आ रही है।सूत्रों की मानें तो जी20 पर हुए अनुमानित 4100 करोड़ रुपए के खर्च में से 98 प्रतिशत से ज्यादा आईटीपीओ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सैन्य इंजीनियर सेवाओं जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा केंद्र के तहत दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी और डीडीए जैसी एजेंसियों ने खर्च किया है।सूत्रों की माने तो ज्यादातर खर्च संपत्ति निर्माण और रखरखाव को लेकर किया गया है. यह एनडीएमसी और लुटियंस जोन क्षेत्रों में किया गया। यही वजह है कि केंद्र सरकार के विभागों ने ज्यादातर खर्च उठाए है।सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में पधारे विदेशी अतिथियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी खर्च हुआ है,जबकि आईटीपीओ ने सिर्फ शिखर सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि विशालकाय कंवेंशन सेंटर भारत मंडपम जैसी दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया है। साथ ही बड़े आयोजनों के लिए हमेशा तैयार रहेंगी।सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन के कुल अनुमानित खर्च में से आईटीपीओ ने क़रीब 3,600 करोड़ रुपये के बिल में से 87त्न से अधिक भुगतान किया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपये और एनडीएमसी ने 60 करोड़ रुपये दिये।केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस, पीडब्लूडी,?मसीडी ,डी डीए और एनएचएचआई सहित दिल्ली सरकार और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर राजधानी में जी20 की शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से पेश किए गए एक दस्तावेज के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ)ने सबसे ज्यादा 3,500 करोड़ रुपया खर्च किया है,इसके बाद 340 करोड़ रुपये का खर्च दिल्ली पुलिस ने उठाया है।

भारत करने पर क्या फिर नोटबंदी होगी......

डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने संविधान में कहा है कि 'इंडिया दैट इज भारत' इस प्रकार, सभी के लिए,इंडिया भारत है और भारत इंडिया है।अगर भाजपा को इंडिया से दिक्कत है तो क्या आप पासपोर्ट से इंडिया हटा देंगे,जहां रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है,क्या करेंसी नोटों से इंडिया शब्द हटाने को तैयार होंगे? अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है, तो क्या आप फिर से नोटबंदी सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि वहां से इंडिया हटाना है,क्योंकि हर करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? देश के कई संस्थानों में इंडिया का जिक्र है। आधार कार्ड, एम्स,आईआईएम, आईआईटी, इसरो और कई अन्य स्थानों पर भी इंडिया का नाम है।आप भारत को कितनी जगहों से हटाना चाहते हैं।आप भारत को क्यों बांटना चाहते हैं कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार 200 से अधिक योजनाएं चला रही है। इनमें से 52 के नाम इंडिया के नाम पर हैं,22 के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं और केवल पांच के नाम ही भारत के नाम पर हैं।

3 वरिष्ठआईपीएस नवंबर, जनवरी में रिटायर होंगे......

छ्ग के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) अशोक जुनेजा अब अगस्त 24 में रिटायर होंगे,अब छ्ग के अन्य वरिष्ठ आईपीएस के बारे में देखें तो विशेष डीजी राजेश मिश्रा जनवरी 24 में तो प्रतिनियुक्ति पर होनेवाले वरिष्ठ आईपीएस रवि सिन्हा जनवरी 24,स्वागत दास,नवम्बर 24 में रिटायर होंगे इसलिये ये तो अगले डीजीपी की दौड़ से बाहर ही हो गये हैं। वहीँ अरुण देव गौतम जुलाई 27, पवन देव जुलाई28, हिमांशु गुप्ता जून 29, एसआर पी कल्लूरी मई 31,प्रदीप गुप्ता जुलाई 31,विवेकानंद सिन्हा जनवरी 32, दीपांशु काबरा जुलाई 34 में रिटायर होंगे। इधर प्रतिनियुक्ति पर होनेवाले जयदीप जुलाई 30 में रिटायर होंगे तो एडीजी पदोन्नत तथा सीबीआई में ज्वाईंट डायरेक्ट पदस्थ अमित कुमार दिसंबर 35 में सेवानिवृत होंगे।

और अब बस...

- बस्तर और सरगुजा संभाग में मिलाकर कुल 26 विधानसभा सीट हैंलेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यहां से केवल एक सीट दंतेवाड़ा ही जीत पाई थी।पर विधायक की नक्सली हमले में मौत के बाद वो सीट भी उपचुनाव के बाद कांग्रेस के कब्जे में चली गई।
- कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों में डेढ़ से दो दर्जन की टिकट काट सकती है?
- भाजपा ने क्या छत्तीसगढ़ विस चुनाव को चुनौती के रूप में ले लिया है...?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा की हार का सेहरा जेपी नड्डा के सिर में बंधेगा : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में अपने नेता मोदी के समान बड़बोलापन दिखा कर गये। उनके पास मोदी सरकार के कामों पर बोलने को कुछ नहीं था। चंद्रयान, जी-20 पर ऐसी बातें कर रहे थे जैसे यह भारत की नहीं भाजपा की उपलब्धि हो, हर साल दो करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगुनी, 100 दिन में महंगाई कम, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर जनता के सवालों का भाजपा अध्यक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र द्वारा किये जा रहे भेदभाव चावल में कटौती, बारदाना में कटौती, 7 लाख प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची पर भाजपा अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोलकर भाजपा के छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को उजागर किया। जिस दिलीप सिंह जूदेव को भाजपा ने जीते जी भुला दिया। जो दिलीप सिंह जूदेव रमन राज के प्रशासनिक अराजकता के शिकार थे। जेपी नड्डा चुनावी लाभ लेने के लिये उनका स्मरण कर रहे थे। जिन पहाड़ी कोरवाओं की भाजपा ने 15 साल उपेक्षा की भाजपा उनका अपने मंच पर बुलाकर राजनैतिक उपयोग करने की कुचेष्ठा कर रही थी। कांग्रेस सरकार ने पहाड़ी कोरवाओं की शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति के लिये काम किया। 190 पहाड़ी कोरवाओं को सीधे अतिथि शिक्षक बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की करारी हार का सेहरा बंधेगा।

सौतेला व्यवहार के कलंक से भाजपा बरी नहीं हो सकती: ठाकुर

रायपुर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता मूर्खतापूर्ण तर्क देकर मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ लगातार की जा रही भेदभाव और सौतेला व्यवहार के काला कलंक से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के 8 लाख से अधिक आवासहीनो के लिए आवास मांगे तो मोदी सरकार आवास क्यों नहीं दे रही? छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ भेदभाव क्यो कर रही? छत्तीसगढ़ से चलने वाली एवं होकर गुजरने वाली लोकल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस कई महीने से रद्द हो रही है। पूर्व आरक्षित टिकट को रद्द कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री को भारी परेशानी हो रही है ऐसा भेदभाव सौतेला व्यवहार मोदी सरकार क्यों कर रही इस पर भाजपा नेता मौन क्यों है? छत्तीसगढ़ का 55000 करोड रुपए केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद प्रदेश के कर्मचारियों के 17400 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र के पास जमा है उसे केंद्र क्यों नहीं दे रही?कोयला रॉयल्टी का 4000 करोड रुपए एवं एफसीआई में जमा चाँवल का बकाया 6000 करोड़ क्यो नही दे रही है?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार का रवैया विपक्षी दलों के खिलाफ रहा है। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां डबल इंजन डबल इंजन का नारा लगाकर उन राज्यों को अतिरिक्त सहायता देती है।

गोयल भाजपा की डूबती नैय्या बचाने झूठ बोलने आये थे : शुक्ला

रायपुर। केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन भाजपा की डूबती नैय्या बचाने पियूष गोयल झूठ बोलने आये थे। जिस पीडीएस के चावल की बात पर पियूष गोयल आरोप लगा रहे है केंद्रीय खाद विभाग के अधिकारियों का दल उसकी जाँच कर के जा चुका है कोई गड़बड़ी नहीं मिली। राज्य सरकार ने खुद जांच करवाया है, राशन दुकानों के स्तर पर जहां गड़बड़ी पायी गयी वहां पर एफआईआर भी दर्ज करवाया गया। देश का सबसे ईमानदार और पारदर्शी राशन वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ की है। जहाँ बिना आधारकार्ड के किसी का राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, हर हितग्राही के राशन कार्ड को आधार से लिंक भी किया गया है। गड़बड़ी चावल वितरण में नहीं भाजपा की नीयत में है ज़ब राज्य में रमन सरकार थी तब 36000 करोड़ का नान घोटाला रमन सिंह उनके परिवार ने किया था इसलिए भाजपा को हर जगह घोटाला ही नजर आता है। पियूष गोयल 86 लाख चावल कि कटौती में भी झूठ बोल कर गए। केंद्रीय खाद्य सचिव ने राज्य के कोटे में कटौती का पत्र भेजा है पूर्व के 86 लाख की स्वीकृति को घटा कर 61 लाख का पत्र भेजा था जिसके संबंध में मुख्यमंत्री ने बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा था।

केंद्रीय मंत्री अव्यवस्था पर कब जवाब देंगे : सुरेंद्र वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि रायपुर एम्स में फैकल्टी और डॉक्टर के 38 प्रतिशत पद रिक्त हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहायक पदों के 39 प्रतिशत पद रिक्त हैं मोदी सरकार की उपेक्षा के चलते रायपुर एम्स में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, मरीजों को भटकना पड़ रहा है लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया विगत 2 महीनों से छत्तीसगढ़ में केवल भाजपा के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया केवल चुनावी लाभ के लिए ही जरूरी है, आम जनता के हित, हक और अधिकार से इनका कोई सरोकार नहीं होता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में चुनाव सह प्रभारी हैं। उनके विगत दो महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ दौरे से जनता को उम्मीद थी कि एम्स रायपुर की बदहाली दूर होगी लेकिन भाजपाइयों का पूरा ध्यान केवल चुनावी लाभ पर ही केंद्रित है। वर्तमान में एम्स रायपुर में डॉक्टर और फैकल्टी के कुल 305 पदों में से 115 पद खाली है इसी तरह से पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ के 3884 के सेटअप में 1497 पद रिक्त है जिसके चलते मरीज स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एम्स रायपुर की स्थापना यूपीए के मनमोहन सिंह सरकार के समय 2011-12 में हुआ था। राज्य सरकार के द्वारा कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल और रेसिडेंशियल कंपलेक्स के लिए 104 एकड़ की जमीन निशुल्क दी गई है।

रेलवे मामले पर मोदी सरकार कर रही सीना जोरी : वैष्णव

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मणी वैष्णव ने कहा कि ने कहा कि निजीकरण की भूख से मोदी सरकार निरंकुश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा जनता की असुविधा दूर करने हेतु किए गए आंदोलन के बाद भी रेलवे सीना तानकर कह रही है कि हम ट्रेन रद्द करेंगे। जिस ट्रेन को कांग्रेस सरकारों में सबसे सुविधाजनक और सस्ता यात्रा का साधन माना जाता था उस साधन से यात्री हलकान हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकारों में रेलवे को विकसित एवं व्यापक बनाकर एक सेवा के रूप में संचालित किया जाता था मगर मोदी सरकार में रेलवे को लाभकारी संस्था बनाने के लिए और उसके बाद अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने के लिए यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है और माल गाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। वृद्ध, विकलांग एवं छात्रों को यात्रा शुल्क में जो छूट दी जाती थी उसे भी मोदी सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का सौंदरयीकरण, कायाकल्प करने की बात कहने वाली मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि देश की जनता स्टेशनों में घूमने के लिए नहीं जाती है बल्कि इसलिए जाती है ताकि वो अपने कार्यस्थल, घर, अपने परिजनों के पास, अस्पताल आदि जगहों पर अविलंब समय पर पहुंच सके। बीते केवल कुछ महीनो में ही 2600 से अधिक ट्रेन रद्द हो चुकी है।

परिवर्तन यात्रा की सफलता से बौखला गई है कांग्रेस: मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर कांग्रेस अफवाह फैला रही थी, मोदी जी के उसी दौरे में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस का झूठ बेनकाब करते हुए कहा है कि मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं और भरोसा है कि आगे भी देते रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने सबके सामने स्पष्ट किया है कि मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। इससे यह आईने की तरह साफ हो गया है कि उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को छोड़कर पूरी कांग्रेस झूठ बोलती है कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है। राज्य शासन की ओर से उप मुख्यमंत्री के कबूलनामे से सत्य सामने आ गया है कि भूपेश बघेल झूठ का निर्माण करते हैं और कांग्रेसियों को उस झूठ का सेल्समैन बना दिया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में सिर से पैर तक लिपटी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता खरपतवार की तरह उखाड़ कर फेंकने तत्पर है तो कांग्रेस अब झूठ की दुकान चला रही है। अब इस दुकान पर भी ताला लगने वाला है। ये वही उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र बनाकर कांग्रेस सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फिर एक साल पहले श्री सिंहदेव ने ही प्रदेश सरकार के एक मंत्रालय से यह कहकर इस्तीफा दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जिन मांगों को लेकर जनघोषणा पत्र बनाया गया था, उसकी पूर्ति नहीं कर पाने के कारण वह इस पद पर नहीं रह सकते।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया। यह कांग्रेस का तुच्छ आचरण और अक्षम्य अपराध है। यह कांग्रेस की कुंठित और निचले स्तर की मानसिकता को दर्शा रहा है। श्री मूणत ने कहा कि कांग्रेस का यह कृत्य कांग्रेस में मची हार की दहशत को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के रायपुर कार्यक्रम को लेकर भी कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने की नाकाम कोशिश की थी। एक राजनीतिक दल ऑफिशियल बयान देकर भ्रम फैलाने का काम करे, इससे अधिक शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। कांग्रेस ऊटपटांग हरकतें करने से बाज नहीं आ रही। यह उनके मुख्यमंत्री के निर्देशन में हो रहा है, जो मानसिक दिवालिएपन का परिचायक है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का घटिया प्रयास किया, बाकायदा कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख ने वीडियो बयान जारी कर प्रधानमंत्री के निश्चित कार्यक्रम के बारे में भ्रम फैलाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ने यह भी झूठ फैलाया कि रायगढ़ के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटने के कारण प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। जबकि, जब यह बयान जारी किया जा रहा था, तब सभा-स्थल पर 1 लाख से अधिक का जनसमूह एकत्रित था। हजारों की संख्या में सारंगढ़ से रायगढ़ मार्ग पर लोग यातायात में फँसे थे और कांग्रेस ने इससे घबराकर झूठा प्रचार करने की घटिया हरकत की। ९

चावल के कोटे को लेकर सीएम बघेल का पीयूष गोयल पर हमला

केवल आरोप लगाने आए हैं, पिछली बार भी केंद्र सरकार की टीम जांच कर चली गई थी

रायपुर. छतीसगढ़ कांग्रेस का चुनाव वॉर रूम बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने फीता काटकर शुभारंभ किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरी पार्टी को बधाई दी. साथ ही चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया. इतना ही नहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के चावल कोटे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है.

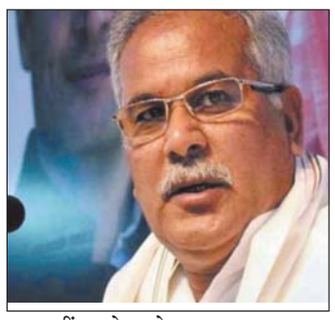

सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के चावल का कोटा

पूरा नहीं करने वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई थी. केवल आरोप लगाने आए हैं, उनकी बातों में दम नहीं है. सभी चीज हमने आधार कार्ड से लिंक की हुई है. राज्य सरकार ने राशन दुकानों का संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई की. चुनाव के लिए अब यह आरोप लगा रहे हैं, उनकी स्थिति केवल यही है.केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में प्रेसवार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भूपेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस सरकार 100 लाख टन चावल दे, हम खरीदने के लिए तैयार हैं. लेकिन सरकार झूठ न बोले. हम 1-1 किलो चावल खरीदने के लिए तैयार हैं.

सीटू ने सांसद को सौंपा ज्ञापन

रायपुर. एम्स में वर्षों से विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की बजाय रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करने पर रोष व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है. इस मांग को लेकर एम्स आउटसोर्सिंग एंप्लॉयज एसोसियेशन ने रायपुर सासंद सुनील सोनी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है.सीटू के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें राज्य सचिव धर्मराज महापात्र, एस सी भट्टाचार्य, एम्स आउटसोर्सिंग एंप्लॉयज एसोसियेशन के अध्यक्ष मारुति डोंगरे, माकपा जिला समिति सदस्य अतुल देशमुख और एम्स के अन्य कर्मचारी शामिल थे. सीटू ने करोना के समय अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले इन कर्मचारियों को स्थाई पद पर नियमित करने की बजाय एम्स में बाहरी भर्ती को रोकने सांसद सुनील सोनी से हस्तक्षेप की मांग की. इन कर्मचारियों ने नियुक्ति के समय सारे परीक्षा देकर एम्स में कार्य आरंभ किया था.

पीएम मोदी के जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाएगी उत्सव: अरुण साव

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को वृहद स्तर पर मनाने की रणनीति बना रही है। इस दिन केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लांच की जाएगी। चुनावी अभियान को तेज करने के लिए भाजपा इस योजना के माध्यम से कामगारों में धोबी, कुम्हार, बढ़ई, मोची व अन्य वर्ग के हितग्राहियों में अपनी पैठ मजबूत करेगी। इस दिन भाजपा के केंद्रीय स्तर के नेता भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। भाजपा ने बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री का जन्म दिवस का जश्न मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 17 सितंबर को है। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक ली थी। इस दौरान पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना को विस्तार देने के लिए कहा है।सभी मोर्चा को अलग-अलग काम सौंपा गया है। जैसे भाजयुमो जिला स्तर पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसी तरह अन्य मोर्चा भी मोर्चे पर डटकर काम कर रहे हैं। गांवों तक चलेगा आयुष्मान भव- अभियान- केंद्र सरकार ने देशभर में आयुष्मान भव- अभियान चलाया चलाने का निर्णय लिया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर होगी सहायिकाओं की भर्ती

रायपुर। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि के बाद एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पदपूर्ति को 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 05 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 सितंबर को आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी। जारी आदेश के अनुपालन में 01 अप्रैल 2023 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रूपए दी जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती